सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" वक्त चाहे जितना भी परखे,
खुद्दार इंसान अपने उसूल नहीं बदलता ...!!

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–211 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 20 अगस्त 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

विश्लेषण

नीतीश कुमार को 'सुपर CM' और 'दूसरा गांधी' बताने की होड़

यूपी में तावड़े और पंजाब में पूनिया पर दांव - जानिए पर्दे के पीछे की राजनीति

आलोक तिवारी / नई दिल्ली

देश के तीन बड़े राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के भीतर सियासी हलचल एक साथ तेज हो गई है। तीनों राज्यों में कारण अलग-अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है - 2027 के चुनावी चक्र से पहले जमीन मजबूत करना और अंदरूनी गुटबाजी को काबू करना।

बिहार: नीतीश कुमार फिर नैरेटिव के केंद्र में

बिहार में भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी जैसे नए चेहरे आए हों, लेकिन सियासी कहानी अब भी नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूम रही है।

पहला संकेत कार्यकर्ताओं के नारे से मिला। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर कार्यकर्ताओं ने "सुपर सीएम जिंदाबाद" के नारे लगाए। दूसरा, संजय झा के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार ने अक्टूबर से पूरे बिहार की राज्य यात्रा पर सहमति दी।

तीसरा और सबसे बड़ा बयान जेडीयू कोटे के मंत्री शैलेश कुमार मंडल का आया। उन्होंने नीतीश की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए कहा कि आजादी के बाद बिहार में अगर कोई दूसरा गांधी हुआ है तो वह नीतीश हैं। इस सबके पीछे दो वजहें साफ दिख रही हैं। एक, जेडीयू अपने पुराने वोटबैंक को यह भरोसा देना चाहती है कि पार्टी की असली पहचान और नीतियां नीतीश कुमार ही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरण में जेडीयू को अपनी प्रासंगिकता साबित करनी है।

दो, भाजपा के साथ गठबंधन में "बड़े भाई" की भूमिका को लेकर चल रही खींचतान। नीतीश को "सुपर सीएम" बताकर जेडीयू यह संदेश दे रही है कि सरकार भले किसी के नाम पर चले, नैतिक और राजनीतिक नेतृत्व नीतीश का ही रहेगा। भाजपा भी फिलहाल इसे टाल रही है क्योंकि बिहार में बिना नीतीश के चुनावी गणित बिगड़ता है। ऐसे में यह होड़ दरअसल गठबंधन के भीतर दबदबे की लड़ाई है।

पंजाब: सतीश पूनिया के कंधे पर सबसे कठिन जिम्मेदारी

भाजपा ने राजस्थान के कद्दावर नेता सतीश पूनिया को पंजाब का नया चुनाव प्रभारी बनाया है। यह फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि 2023 में राजस्थान में हार के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा बरकरार रखा।

पूनिया का ट्रैक रिकॉर्ड इसका कारण है। हरियाणा में उन्होंने जाट-गैर जाट समीकरण साधकर भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाने में भूमिका निभाई। बिहार के नवादा में 6 में से 5 सीटें जिताने में भी उनका योगदान माना जाता है। उन्होंने खुद कहा कि "भाजपा के सीसीटीवी कैमरे हर कार्यकर्ता की परफॉर्मेंस देखते हैं।" यानी योग्यता को पार्टी नजरअंदाज नहीं करती।

लेकिन पंजाब की जमीन बिल्कुल अलग है। 117 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा अकेले दम पर खड़ी है। किसान आंदोलन की नाराजगी, सीमांत राज्य की सुरक्षा और क्षेत्रीय दलों का दबदबा - ये सभी चुनौतियां पूनिया के सामने हैं।

पूनिया की तैनाती का मतलब साफ है। भाजपा पंजाब में शून्य से शुरूआत कर एक नया सामाजिक समीकरण बनाना चाहती है। शहरी हिंदू वोट के साथ-साथ दलित सिख और ओबीसी वर्ग में पैठ बनाने की कोशिश होगी। यह काम एक-दो चुनाव में नहीं होगा, इसलिए नेतृत्व ने लंबी रेस के घुड़सवार पूनिया को चुना है।

उत्तर प्रदेश: तावड़े से साधा जाएगा योगी-शाह के बीच समन्वय

2024 के लोकसभा नतीजों के बाद यूपी में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता संगठन और सरकार के बीच तालमेल की है। इसी खाली जगह को भरने के लिए महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को मैदान में उतारा गया है।

तावड़े की सबसे बड़ी ताकत उनका बैलेंस है। वे अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनके नाम पर आपत्ति नहीं है। पिछले कुछ महीनों में यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार जैसे अहम फैसले दिल्ली से लखनऊ तक तावड़े के जरिए ही तय हुए हैं।

उनके सामने तीन मोर्चे हैं। पहला, समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को 2024 के प्रदर्शन के बाद और धारदार बनने से रोकना। दूसरा, सरकारी नौकरी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं में जो असंतोष है उसे ठंडा करना। तीसरा और सबसे जरूरी, पार्टी के भीतर ठाकुर, ब्राह्मण और कुर्मी गुटों के बीच बढ़ती खींचतान को साधना। 2027 में जीत की हैट्रिक के लिए इन तीनों वर्गों को साथ रखना जरूरी है।

तावड़े को "सेतु" की भूमिका दी गई है। न तो वे सरकार चलाएंगे और न ही संगठन के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन दोनों के बीच संवाद की सबसे मजबूत कड़ी वही होंगे।

तीनों राज्यों की तस्वीर अलग है लेकिन रणनीति एक जैसी। बिहार में गठबंधन को जोड़े रखने के लिए पुराने चेहरे को फिर चमकाया जा रहा है। पंजाब में हार के बावजूद भरोसेमंद रणनीतिकार को भेजकर नई जमीन तैयार की जा रही है। और यूपी में सत्ता और संगठन के बीच खाई पाटने के लिए एक समन्वयक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2027 अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने अभी से तीनों राज्यों में अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि "सुपर सीएम" का नैरेटिव कितना चलता है, पूनिया पंजाब में आधार बना पाते हैं या नहीं, और तावड़े यूपी में सभी गुटों को एक मंच पर ला पाते हैं या नहीं।

बिहार में पुलिसिया कार्रवाई पर गरमाई राजनीति

विशेष संवाददाता संदीप सिंह / पटना / नई दिल्ली / लखनऊ

तेजस्वी का राजभवन मार्च, यूपी में अखिलेश का 'चवन्नी-रुपया' तंज

देश के तीन बड़े राज्यों में छात्र आंदोलन और चुनावी गोलबंदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से सड़क से लेकर अदालत तक हंगामा है, दिल्ली में PMO केंद्रीय मंत्रियों का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में सपा-एनडीए के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।

बिहार: सिवान फायरिंग के बाद तेजस्वी सड़कों पर, सरकार ने किए प्रशासनिक बदलाव

बिहार के सिवान जिले में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा फायरिंग के आरोपों के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आठ राउंड फायरिंग का दावा किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने अदालत में चार राउंड गोली चलने की बात स्वीकारी है। घटना के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही सिवान के एसपी और डीएम का तबादला कर उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

इस मुद्दे को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने पहले अस्पताल जाकर घायल छात्रों से मुलाकात की और फिर पटना में विशाल राजभवन मार्च का नेतृत्व किया। तेजस्वी ने कहा कि युवाओं के भविष्य, रोजगार और पारदर्शी परीक्षाओं की मांग को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा और किसी भी दमन से वे पीछे नहीं हटेंगे। राजद सांसद मनोज झा ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।

राजस्थान और UP में भी छात्र सड़कों पर, केंद्रीय मंत्री ने पुलिस कार्रवाई का किया बचाव

छात्र असंतोष सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी छात्र स्कूल-कॉलेजों में सुविधाओं की कमी और परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली के जंतर-मंतर और अन्य जगहों पर हुए प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पूरे संयम से स्थिति संभाली और किसी अप्रिय घटना या गंभीर चोट से प्रदर्शनकारियों को बचाया।

उत्तर प्रदेश: अखिलेश का जयंत चौधरी पर 'चवन्नी-रुपया' वाला तंज

उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीए और आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर हमला बोला। अखिलेश ने भाजपा और उसके सहयोगियों निषाद पार्टी, अपना दल और सुभासपा के बीच सीट बंटवारे पर सवाल उठाए। जयंत चौधरी के पाला बदलने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजकर राजनीतिक रूप से 'रुपया' बनाया था, लेकिन वे एनडीए में चले गए। अखिलेश के इस बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और अन्य समुदायों के बीच चुनावी ध्रुवीकरण की चर्चा तेज हो गई है।

भिलाई की शिवमहापुराण कथा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज

सावन में एक ही जगह लगातार तीसरी बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा और 5 विशाल अस्थाई पंडाल के नाम पर बना रिकॉर्ड

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में आयोजित शिवमहापुराण कथा ने इतिहास रच दिया है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दयासिंह के नाम यह कथा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। एक ही जगह पर, एक ही महीने यानी सावन में, एक ही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले द्वारा लगातार तीसरी बार कथा आयोजित करने और 5 विशाल अस्थाई पंडाल बनाने के नाम पर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है।

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशियन हेड मनीष विश्नोई नई दिल्ली ने यह सर्टिफिकेट और मेडल बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष दयासिंह को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की उपस्थिति में प्रदान किया। इस गौरवशाली क्षण के लाखों शिवभक्त साक्षी बने।

एशियन हेड मनीष विश्नोई ने कहा कि "बिना कोई सूचना दिए हमारी टीम पिछले 3 दिनों से रिसर्च कर रही थी। लाखों शिवभक्तों की आस्था और उनका आना-जाना ऐसा है जो किसी अन्य कथा में देखने को नहीं मिलता।"

इस उपलब्धि पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सरोज पांडेय, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, भिलाई महापौर नीरज पाल, दुर्ग महापौर अलका बाघमार, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, समाजसेवी गोपाल खंडेलवाल, जी सुरेश बाबू, रमन साहनी, प्रकाश पारख, संतोष अग्रवाल, रतन अग्रवाल, सुनील गोयल, दिलीप अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने दयासिंह को बधाई दी।

सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को लताड़ा

पंडित मिश्रा ने सोशल मीडिया पर सनातन हिंदू धर्म का उपहास करने वालों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, "सनातन के सभी त्योहार मनुष्य ने नहीं, परमात्मा ने बनाए हैं। किसी धर्म में इतना दम नहीं। सती की कथा बताती है कि पत्थर को पूजन कर महादेव बना देने का बल केवल सनातन में है।"

भगवान शिव के 7 प्रश्न - जीवन के लिए जरूरी उत्तर

कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव और माता सती के विवाह की कथा सुनाई। दक्ष प्रजापति द्वारा ली गई परीक्षा में 7 ब्राह्मणों ने शिवजी से 7 प्रश्न किए। पंडित मिश्रा ने कहा कि इनके उत्तर हमें जीवन में उतारने चाहिए:

सबसे बड़ा धन - संतोष
सबसे बड़ा रोग - क्रोध
सबसे बड़ा सुख - सेवा
सबसे बड़ा तीर्थ - माता-पिता की सेवा
सबसे बड़ा पाप - अहंकार
सबसे बड़ा पति - जो पत्नी का मान-सम्मान रखे और सुख-दुख में साथ दे

प्यार में नफरत, प्रेम में समर्पण

पंडित मिश्रा ने कहा, "प्यार में नफरत होती है, प्रेम में समर्पण। सच्चा प्रेम देखना है तो माता सती और शिवजी को देखो। सती यज्ञकुंड में जल गईं, फिर भी भोलेनाथ आज भी अपने तन पर उनकी राख लपेटे रहते हैं।"

बेलपत्री का एक अंश भी देता है फल

उन्होंने कहा कि बेलपत्री के हजार टुकड़े भी हों और हम भाव से एक अंश भी ग्रहण कर लें तो फल जरूर मिलता है। माता शबरी की कथा सुनाते हुए मंदिर में झाड़ू लगाने और फूल तोड़कर चढ़ाने के महत्व को भी बताया। लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं ने कथा सुनी।

भिलाई टाइम्स न्यूज के पेज पर फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर 10 हजार की मांग

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

तकनीकी जांच से बिहार का युवक गिरफ्तार, iPhone 16 जप्त

सुपेला थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भिलाई टाइम्स न्यूज के इंस्टाग्राम पेज को निशाना बनाकर पेज बंद करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये मांगे थे।

क्या था मामला

भिलाई टाइम्स न्यूज के संचालक यशवंत साहू ने थाना सुपेला में शिकायत की थी कि 25 से 26 जुलाई 2026 के बीच उनके इंस्टाग्राम पेज पर लगातार फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी गईं। पेज पर 32,000 फॉलोवर्स हैं और स्ट्राइक से पेज डिलीट होने का खतरा बन गया था। ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करने पर स्ट्राइक हटाने के नाम पर 10 हजार रुपये की मांग की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1061/2026, धारा 308(2), 351(4) बीएनएस और धारा 66डी आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

इस तरह पकड़ा गया आरोपी

विवेचना में साइबर सेल की मदद से व्हाट्सएप नंबर, ई-मेल आईडी, इंस्टाग्राम/फेसबुक अकाउंट और आईपी की तकनीकी जानकारी जुटाई गई। इसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस टीम ने 17 अगस्त को आरोपी के निवास पर धारा 35 बीएनएस का नोटिस दिया। नोटिस पर 19 अगस्त को आरोपी थाना सुपेला उपस्थित हुआ। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त iPhone 16 भी जप्त किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है।

आरोपी का नाम

अनीश कुमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम उसरी चकिया, थाना महेन्द्रीया, जिला अरवल, बिहार। हाल पता आईओएस तथावडे, थाना वाकड, जिला पुणे, महाराष्ट्र।

मॉडस ऑपरेंडी

आरोपी सोशल मीडिया न्यूज पेजों को टारगेट कर फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता था। फिर पेज बंद होने का डर दिखाकर स्ट्राइक हटाने के नाम पर पैसे मांगता था।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या ई-मेल पर कॉपीराइट, अकाउंट बंद होने जैसी समस्या के नाम पर कोई पैसे मांगे तो भुगतान न करें। प्लेटफॉर्म की आधिकारिक प्रक्रिया अपनाएं और साइबर अपराध होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।

सराहनीय कार्य

कार्रवाई में थाना प्रभारी एस.एन. सिंह, उप निरीक्षक पारस सिंह, प्रधान आरक्षक अमर सिंह और आरक्षक रवि साहू की भूमिका रही।

द्वादश ज्योतिर्लिंग महारुद्र अभिषेक से शिवभक्ति में सराबोर हुआ दुर्ग

सतरूपा शीतला मंदिर में माँ शक्ति स्वरूपा समिति का भव्य आयोजन, विधायक-महापौर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

सावन और नागपंचमी के पावन अवसर पर दुर्ग नगरी सोमवार को शिवभक्ति में डूब गई। माँ शक्ति स्वरूपा समिति, दुर्ग द्वारा सतरूपा शीतला मंदिर परिसर में द्वादश ज्योतिर्लिंग महारुद्र अभिषेक का भव्य आध्यात्मिक आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूपों का एक साथ विधि-विधानपूर्वक अभिषेक इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा।

मंदिर परिसर सुबह से ही भक्तों से भरा रहा। वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखध्वनि और "हर-हर महादेव", "बम-बम भोले" के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने जल, दुग्ध और पूजन सामग्री से ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक कर मनोकामनाएं मांगी। भिलाई के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हेमंत शर्मा और उनकी टीम ने विद्वान आचार्यों के साथ शास्त्रोक्त विधि से महारुद्र अभिषेक सम्पन्न कराया। मंत्रों की गूंज से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया।

गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर की महापौर श्रीमती अलका बागमार, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण वोरा, वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश बरमेचा एवं श्रीमती मंजू बरमेचा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पूजा में सहभागिता की और समिति द्वारा किए गए आयोजन की सराहना की।

समिति ने जताया आभार

माँ शक्ति स्वरूपा समिति की संयोजिका डॉ. भावना दिवाकर ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा और श्रद्धालुओं की आस्था से यह आयोजन भव्य बन सका। उन्होंने कहा कि सावन जैसे पवित्र अवसरों पर ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ते हैं। समिति का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं, बल्कि समाज में एकता और संस्कार की भावना को मजबूत करना भी है।

आयोजन की सफलता में समिति की सदस्यों कुलविंदर कौर, गीता वर्मा, रिंकी साहू, वारुणी डेहरे, बसंती साहू, रंजीता, मीनू मिंज, पार्वती पंडित, रजनी मिश्रा, अर्चना साहू, विभा मिश्रा, श्वेता साहू, श्रद्धा साहू, शीतल तिवारी, प्रीति, साधना शर्मा, खुशबू सिंह सहित सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समिति ने व्यवस्थाओं, अतिथि सत्कार और पूजा की तैयारियों में सराहनीय भूमिका निभाई। अंत में पूरा मंदिर परिसर भक्तों के जयकारों से गूंजता रहा। यह आयोजन दुर्ग के धार्मिक-सामाजिक जीवन में एक स्मरणीय अध्याय बन गया।

खास खबर

महिला पर बैटरी का केमिकल फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, बातचीत बंद करने से नाराज था महेश दास, आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / नंदिनी अहिवारा

ग्राम अरसनारा के पास एक महिला पर बैटरी में पाए जाने वाले केमिकल का छिड़काव कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में नंदिनी नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जप्त की गई है।

17 अगस्त 2026 को कारंजा भिलाई निवासी पीड़िता अपने परिचित के साथ कांवड़ यात्रा के लिए ग्राम कोडिया आई थी। इसी दौरान ग्राम कारंजा भिलाई निवासी आरोपी महेश दास उम्र 30 वर्ष महिला से बातचीत बंद किए जाने से नाराज था। इसी रंजिश के चलते वह ग्राम अरसनारा के पास पहुंचा और टिन के डिब्बे में रखा बैटरी का केमिकल पीड़िता पर छिड़क दिया। इससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई घटना की सूचना पर थाना नंदिनी नगर में अपराध क्रमांक 271/2026, धारा 124(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और पीड़िता का उपचार कराने के साथ अस्पताल में उससे जानकारी ली।

पुलिस टीम ने रातभर घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम कारंजा भिलाई में छिपा है। सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी महेश दास को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पुलिस को सौंप दी, जिसे जप्त कर लिया गया। केमिकल युक्त एक डब्बा भी बरामद हुआ। आरोपी को 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। आरोपी मोटरसाइकिल से ग्राम अरसनारा पहुंचा था। साथ में लाए टिन के डिब्बे में रखे बैटरी के केमिकल को महिला पर छिड़ककर वह मौके से फरार हो गया था।

विधायक चंद्राकर ने मूक-बधिर आवासीय विद्यालय के बच्चों को वितरित की पुस्तकें और बैग

दुर्ग। दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर धनोरा स्थित "तारे जमीन पर" मूक-बधिर बच्चों के आवासीय विद्यालय, हरिशीकेश एजुकेशन सोसायटी पहुंचे। इस अवसर पर विद्यालय में कक्षा पहली से पांचवीं तक अध्ययनरत 32 मूक-बधिर बच्चों को पुस्तकें एवं बैग वितरित कर विधायक श्री चंद्राकर ने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए विधायक चंद्राकर ने कहा कि "बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखकर मन को बेहद प्रसन्नता हुई। शिक्षा और सहयोग के छोटे-छोटे प्रयास ही बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बनते हैं। ये बच्चे विशेष हैं और इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि हरिशीकेश एजुकेशन सोसायटी द्वारा मूक-बधिर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं आवासीय सुविधा देकर समाज सेवा का अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। ऐसे प्रयास ही समाज को संवेदनशील और समावेशी बनाते हैं। विधायक ने आश्वस्त किया कि विद्यालय के विकास एवं बच्चों की सुविधाओं के लिए हर संभव सहयोग राज्य सरकार एवं उनके द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संस्था की डायरेक्टर गीता विश्वास, प्राचार्य देवोप्रिया घोष, लातेश्वरी ठाकुर, प्रीति साहू, गुंजा राव, गायत्री साहू, भद्राशीला पजारे, डॉली देवांगन, कुसुमलता सहित समस्त शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

इंदिरा मार्केट के सार्वजनिक शौचालयों का सभापति व प्रभारी ने किया निरीक्षण

जर्जर मूत्रालयों के जीर्णोद्धार और नियमित साफ-सफाई के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा मार्केट क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन में निगम सभापति श्याम शर्मा एवं लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर निरीक्षण किया। इस दौरान ज्ञानेश्वर ताम्रकर, गुलशन साहू, मनीष कोठारी सहित निगम के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, उपअभियंता पंकज साहू सहित अधिकारियों ने इंदिरा मार्केट क्षेत्र में स्थित विभिन्न सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की स्थिति का जायजा लिया।

सभापति श्याम शर्मा ने जर्जर एवं खराब स्थिति वाले सार्वजनिक मूत्रालयों को चिन्हांकित कर उनके जीर्णोद्धार तथा आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्र में आने वाले नागरिकों एवं व्यापारियों को बेहतर और स्वच्छ सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है।

निरीक्षण के दौरान इंदिरा मार्केट के व्यापारी नितेश पटेल, जयंत ताम्रकर सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। व्यापारियों ने क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालयों की जर्जर स्थिति, साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं से सभापति एवं निगम अधिकारियों को अवगत कराया। सभापति श्याम शर्मा एवं लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि जर्जर सार्वजनिक मूत्रालयों के सुधार एवं आवश्यक निर्माण कार्य को जल्द कराया जाएगा, ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सार्वजनिक शौचालयों की रोजाना होगी सफाई

स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त,सभापति श्याम शर्मा ने निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारियों को क्षेत्र के सभी सार्वजनिक एवं सुलभ शौचालयों की रोजाना नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार जैसे व्यस्त क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। शौचालयों में साफ-सफाई, पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि आम नागरिकों एवं व्यापारियों को स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

रिमझिम सावन-2026 का भव्य आगाज कल से

नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी रिमझिम सावन-2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सावन के उल्लास, उमंग और महिलाओं की सहभागिता को समर्पित यह उत्सव 21 अगस्त से प्रारंभ होगा। आयोजन में महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं आकर्षक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रिमझिम सावन-2026 के शुभारंभ अवसर पर समाज सेविका श्रीमती कौशल्या देवी साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। वहीं भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सरोज पाण्डेय अति-विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार करेंगी। **महिलाओं के लिए विविध मनोरंजक प्रतियोगिताएं** : महापौर अलका बाघमार के मार्गदर्शन में आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सांस्कृतिक विभाग प्रभारी श्रीमती हर्षिका सांभव जैन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग प्रभारी श्रीमती शशि साहू ने महिला पार्षदों तथा निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की। उत्सव के दौरान महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़, मटकी फोड़, आलू दौड़, कंचा-चम्मच दौड़, बिंदी लगाओ प्रतियोगिता सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने की इच्छुक महिलाएं सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक अपना पंजीयन करा सकेंगी।

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 5 जनवरी को ही मनाया जाएगा

सभी गुरुद्वारा कमेटियों की अहम बैठक में सर्वसम्मति से हुआ निर्णय

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंघ साहिब जी के प्रकाश पर्व मूल नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 5 जनवरी को ही मनाने को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग एवं सिख युथ सेवा समिति भिलाई के साथ-साथ सभी गुरुद्वारे के सिंघ साहिबान की उपस्थिति में सिख पंचायत अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया। सिख पंचायत महासचिव गुरुनाम सिंह ने बताया कि 5 जनवरी की तिथि को लेकर नानकशाही कैलेंडर (संशोधित/मूल) के अनुसार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 5 जनवरी को निर्धारित है।

बैठक में तिथियों की एकसमता और पंथक परंपरा को लेकर कि प्रकाश पर्व 5 जनवरी को मनाना सर्व सहमति से तय हुआ, एवं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन एक सप्ताह पूर्व निकाला जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित सिख युथ सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू एवं कोषाध्यक्ष मलकीत सिंह द्वारा 5 जनवरी को प्रकाश पर्व की तिथि तय करने की सहमति दी। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पलविंदर सिंह रंधावा, बलदेव सिंह, हरभजन सिंह चहल, जसवीर सिंह सैनी, हरमिंदरसिंह सैनी, सरबजीत सिंह नंदरा, गुरदेव सिंह, कुलवंत सिंह, बीबी कुलवंत कौर, गुरमीत सिंह चहल, तेजिंदर सिंह हुंदल, बलजिंदर सिंह कलेर, गुरमीत सिंह सोखी, सौदागर सिंह, निर्मल सिंह रंधावा, सुखदेव सिंह लाडी, हरपाल सिंह हैप्पी, पवित्र सिंह, त्रिलोचन सिंह सिद्धू, जगजोत सिंह बिंद्रा, इंद्रपाल सिंह सैनी, जसवंत सिंह, कुलदीप सिंह, जोगिंदर सिंह, स्वरूप सिंह, पुष्पक सिंह, जसवीर सिंह वेगल, अमृतपाल सिंह, मुखविंदर सिंह, परमजीत सिंह, रौनक सिंह, निशान सिंह, अजीत सिंह खैरा, मलकीत सिंह, बलविंदर सिंह, जसेड़ा अनूप सिंह, बलकार सिंह, अमृतपाल सिंह, गुरविंदर सिंह, बलविंदर कौर, सुखविंदर कौर एवं अन्य सदस्य उपस्थित हुए।

नगर निगम भिलाई ने गंदगी फैलाने पर 3 हजार रुपये का वसूला जुर्माना

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम की टीम ने जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25 जवाहर नगर गौरव पथ मार्ग के पास गंदगी फैलाते पाए जाने पर रजनी ट्रेडर्स के खिलाफ चालानी कार्रवाई की।

निगम अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया कि प्रतिष्ठान द्वारा आसपास कचरा फैलाया जा रहा था। इसके बाद संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 3,000 रुपये का जुमार्ना वसूल किया गया।

निगम प्रशासन ने प्रतिष्ठान संचालकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाएं और शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

शासन निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया बेचने वाला संचालक गिरफ्तार

ऋषभ राज फर्टिलाइजर, कुम्हारी के संचालक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक बेचने के मामले में कुम्हारी पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए फर्टिलाइजर दुकान के संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार ऋषभ राज फर्टिलाइजर, कुम्हारी के संचालक मनीष गुप्ता (50 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 15, शंकर नगर, कुम्हारी द्वारा किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर 13 जून 2026 को फर्टिलाइजर निरीक्षक सरिता चहू ने जांच दल के साथ संबंधित प्रतिष्ठान का निरीक्षण

किया। जांच के दौरान किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक विक्रय किए जाने से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए।

निरीक्षण के बाद फर्टिलाइजर निरीक्षक द्वारा थाना कुम्हारी में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच रिपोर्ट एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर 18 अगस्त 2026 को आरोपी मनीष गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपी द्वारा किसानों की आवश्यकता से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्री यूरिया एवं अन्य उर्वरक शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचे जा रहे थे। निर्धारित मूल्य का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

ऋषभ राज फर्टिलाइजर, कुम्हारी, थाना कुम्हारी क्षेत्र, जिला दुर्ग। आरोपी मनीष गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, शंकर नगर, कुम्हारी, जिला दुर्ग। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना कुम्हारी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं जांच के आधार पर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

दुर्ग पुलिस ने किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई दुकानदार शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया, उर्वरक अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित विभाग अथवा पुलिस को दें। निर्धारित मूल्य एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नया बस स्टैंड के पास मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट करने वाले 4 आरोपी पकड़े गए

नया बस स्टैंड दुर्ग के पास कार में बैठे युवकों से गाली-गलौज, मारपीट, कार में तोड़फोड़ तथा कटर की नोक पर मोबाइल और नगदी लूटने के मामले में पद्मनाभपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर सभी चार आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें दो बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी सूरज साहू (31 वर्ष), निवासी बोरसी पद्मनाभपुर ने थाना पद्मनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 18 अगस्त 2026 की तड़के करीब 3 से 3:30 बजे वह अपने साथी रवि साहू, राहुल साहू और राजा के साथ बलेनो कार क्रमांक CG11/AN/2387 में नया बस स्टैंड के पास बैठा था। इसी दौरान अर्बानिया मिनी बस क्रमांक CG07CY9600 वहां आकर रुकी। बस का दरवाजा जोर से खुलने के कारण कार में डेंट लग गया। इस बात को लेकर प्रार्थी के साथी रवि ने संभतकर दरवाजा खोलने की बात कही, जिसके बाद बस में सवार चार लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने एकराय होकर गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिसमें रवि साहू और राजा को चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक मारपीट के दौरान आरोपियों ने धारदार कटर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और प्रार्थी का सैमसंग मोबाइल तथा उसके साथी का आईक्यू मोबाइल लूट लिया। इसके बाद आरोपियों ने बलेनो कार के कांच तोड़ दिए और डैशबोर्ड में रखे 5 हजार रुपये नगद निकालकर अर्बानिया मिनी बस से मौके से फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 470/2026 के तहत धारा 309(6), 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस टीम ने त्वरित पतासाजी करते हुए घटना में शामिल सभी चार आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान कोमल निषाद (32 वर्ष), निवासी कुंदरा पारा दुर्ग और पूरन निषाद (19 वर्ष), निवासी कुंदरा पारा दुर्ग के रूप में हुई है। वहीं दो विधि से संघर्षरत बालकों की पहचान उनकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए एक सैमसंग मोबाइल और एक आईक्यू मोबाइल बरामद किया है।

उत्कृष्ट शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों से संवर रहा छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय आईबीसी 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 कार्यक्रम में हुए शामिल, प्रदेश के सभी संभागों की टॉपर बेटियों को किया सम्मानित, प्रदान की स्कॉलरशिप

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

शिक्षा किसी भी समाज और राज्य के विकास का मूल आधार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देती है और रोजगार उनके सपनों को साकार करने का मजबूत आधार बनता है। छत्तीसगढ़ सरकार उत्कृष्ट शिक्षा, आधुनिक तकनीक और रोजगार के नए अवसरों के माध्यम से प्रदेश के बच्चों और युवाओं का भविष्य संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों से लेकर सुदूर वनांचलों तक बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की तकनीक के लिए तैयार किया जा रहा है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के जोरा स्थित एक निजी होटल में आयोजित आईबीसी24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टॉपर बेटियों को सम्मानित कर उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इन बेटियों की उपलब्धि उनके परिवार और विद्यालय के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। कार्यक्रम में कक्षा बारहवीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बेमेतरा की ओमनी वर्मा को मुख्यमंत्री श्री साय ने एक लाख रुपए का चेक और सम्मान पत्र प्रदान किया। उनके विद्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्या विद्यालय, बेमेतरा को भी एक लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्टजनों का सम्मान किया तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित

पुस्तक मेधा का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिभावान विद्यार्थियों से संवाद करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि होनहार बेटियों के बीच आकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गृहग्राम बगिया की प्राथमिक शाला में हुई। पांचवीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए उन्हें अपने गांव से कुछ दूर दूसरे गांव जाना पड़ा था। उस समय गांव के स्कूल का भवन मिट्टी का था और उसकी मरम्मत में गांव के लोग मिलकर सहयोग करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने राज्य निर्माण के 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज प्रदेश में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक संस्थानों का व्यापक नेटवर्क विकसित हुआ है। प्रत्येक विकासखंड में महाविद्यालय उपलब्ध हैं। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान आज छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। इससे प्रदेश के बच्चों को अपने राज्य में ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति की स्थापना के साथ शिक्षा का नया अध्याय भी शुरू हो रहा है। जगरगुंडा और ओरछा जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी की शुरूआत की जा रही है। जिन इलाकों में कभी परिस्थितियों के कारण शिक्षा तक पहुंच चुनौतीपूर्ण थी, वहां अब बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना और अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास केवल शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सुविधाएं और वातावरण उपलब्ध कराना भी है। प्रदेश में 34 स्थानों पर नालंदा परिसर विकसित किए जा रहे हैं, जहां युवाओं को शांत और सुविधायुक्त वातावरण में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश की राजधानी नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के जनजातीय युवाओं के लिए 200 बिस्तरों वाला ट्राइबल यूथ हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। यहां विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस

एआई मिशन से भविष्य की तकनीक के लिए तैयार होगी नई पीढ़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है। राज्य के विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नई तकनीकों से परिचित हों और भविष्य की संभावनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़ एआई मिशन शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उन्हें भविष्य के रोजगार और नवाचार के अवसरों के लिए तैयार करना है।

बस्तर में शांति के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का नया दौर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर के विकास में बड़ी बाधा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सुरक्षा बलों के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। इसके परिणामस्वरूप बस्तर में शांति और विश्वास का वातावरण मजबूत हुआ है तथा विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर के 92 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह बदलते बस्तर की नई तस्वीर है। नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, राशन और अन्य बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत 34 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और लगभग 40 हजार लोगों का उपचार किया गया है। बस्तर मुन्ने और नियद नेल्लानार जैसी पहलों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक लाख से अधिक लोगों के राशन कार्ड भी बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि धुड़मारास में विदेशी पर्यटक होमस्टे में रहकर स्थानीय जनजातीय जीवन, संस्कृति, खान-पान और परंपराओं को करीब से जान रहे हैं। राज्य सरकार बस्तर सहित प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में होमस्टे को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए ऋण एवं सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत माध्यम बनाने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति में भी पर्यटन को शामिल किया गया है।

निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा के साथ युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर तैयार करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 को देश-विदेश में सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। नई नीति के अंतर्गत अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हुए हैं और इन निवेश प्रस्तावों का प्रभाव धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है, जो स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराएंगी। एक हजार स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमियों के लिए वीस्पोक नीति के अंतर्गत विशेष इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। बारिश के मौसम के बाद प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जाएगा, जिनके माध्यम से युवाओं को विभिन्न उद्योगों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से सीधे जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप से सम्मानित सभी छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और निरंतर मेहनत करें। राज्य सरकार उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, तकनीक और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज, गोयल ग्रुप एंड कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल, राजीव गोयल, दिनेश गोयल, रविकांत मित्तल सहित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खास खबर

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ, तस्वीरों में उतरा छत्तीसगढ़, फोटो जर्नलिस्टों का हुआ सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर प्रेस क्लब में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की प्रकृति एवं पर्यावरण कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं संस्कृति एवं परंपरा कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की महक महसूस की जा सकती है। समाचार एवं जनसरोकार कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है। इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देते हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों के लिए भी ओपन कैटेगरी में भागीदारी का अवसर दिया। इस श्रेणी में 35 से अधिक प्रतिभागियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं।

तस्वीर पत्रकारिता की अधूरी खबर को पूरा करती है : मोहन तिवारी

रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दृश्य संवाद केवल एक फोटो प्रदर्शनी नहीं, बल्कि तस्वीरों के माध्यम से समाज और समय से संवाद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता, फोटो जर्नलिस्ट साथियों के बिना अधूरी है। खबर को जीवंतता और प्रभाव देने में एक तस्वीर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त तस्वीर के लिए कई बार लंबे कैप्शन की जरूरत नहीं होती। बिना किसी कैप्शन के भी तस्वीर अपने आप में पूरी खबर कहने की ताकत रखती है। फोटो जर्नलिस्ट जिस क्षण को कैमरे में कैद करता है, वह आने वाले समय में उस घटना का दस्तावेज बन जाता है। उन्होंने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब आने वाले वर्षों में भी विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी और फोटो जर्नलिस्ट गतिविधियों की परंपरा को आगे बढ़ाएगा।

कार्यक्रम में रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू, भूपेश जांगड़े, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट गोकुल सोनी, राजकुमार चतुर्वेदी, नरेंद्र बंगाले, प्रदीप डडसेना, पंकज चौहान, फोटो जर्नलिस्ट प्रकोष्ठ के संयोजक दीपक पांडे, दीपेंद्र सोनी, रमन हलवाई, जय गोस्वामी, सागर फारीकार, पंकज सिंह, विजय देवांगन मनोज देवांगन विनय घाटगे, हेमंत गोस्वामी किशन लोखंडे त्रिलोचन मानिकपुरी, राजेश सोनकर सहित बड़ी संख्या में फोटो जर्नलिस्ट एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने स्रोत महोत्सव 2026 और राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, कृषि और समृद्धि की जीवनधारा हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने में प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिन नदियों ने हमारी सभ्यता को पोषित किया और हमें समृद्धि दी, उनका संरक्षण हम सभी का साझा दायित्व है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के ओमाया गार्डन में आयोजित स्रोत महोत्सव 2026 एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश की नदियों के उद्गम स्थलों एवं जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण, जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने तथा नदी संरक्षण को व्यापक जन अभियान का स्वरूप देना है। कार्यशाला में जल संरक्षण, नदी पुनरुद्धार और जल प्रबंधन से जुड़े विषय विशेषज्ञों के साथ राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा। इसी भावना के साथ राज्य सरकार नदियों के उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और जनभागीदारी के समन्वय से व्यापक कार्ययोजना पर आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। महानदी सहित प्रदेश की अनेक नदियों ने कृषि, आजीविका और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया है। नदियों का अस्तित्व उनके उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के स्वास्थ्य पर निर्भर है। इसलिए नदी संरक्षण का कार्य केवल उसके प्रवाह क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। हमें नदी के स्रोत से लेकर उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समझकर संरक्षण की समग्र योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। स्रोत महोत्सव में विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे धरातल पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

पांच प्रमुख स्तंभों पर आगे बढ़ेगा नदी संरक्षण अभियान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में नदी संरक्षण के लिए मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जनभागीदारी और कार्ययोजना के पांच प्रमुख स्तंभों पर काम किया जाएगा। प्रत्येक नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से मानचित्रण किया जाएगा। नदी का उद्गम कहां है, उसके प्रवाह क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, भू-उपयोग में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं और किन कारणों से नदी

के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है - इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक मानचित्रण और अध्ययन के आधार पर नदी के पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी। इसमें वन एवं वनस्पति संरक्षण, मृदा क्षरण की रोकथाम, पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, आवश्यकतानुसार नई जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण और भू-जल पुनर्भरण जैसे कार्य शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाजल हमारे नदी तंत्र और भू-जल का मूल आधार है। इसलिए बारिश के पानी को तेजी से बहकर निकल जाने देने के बजाय उसे अधिक से अधिक मात्रा में धरती के भीतर पहुंचाने के उपाय करने होंगे। इससे भू-जल स्तर में सुधार होगा, जल स्रोतों को पुनर्जीवन मिलेगा और नदियों में लंबे समय तक जल प्रवाह बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

नदी संरक्षण को बनाना होगा जन आंदोलन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल संरक्षण का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। नदियों के किनारे बसे गांवों और वहां रहने वाले लोगों का नदी से सीधा संबंध है, इसलिए उन्हें नदी संरक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख भागीदार बनाना होगा। उन्होंने जिला स्तरीय समितियों के सदस्यों से कहा कि नदियों के किनारे बसे गांवों में स्थानीय समितियां गठित कर पंचायतों के सहयोग से नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्य आगे बढ़ाए जाएं। स्थानीय समुदाय को नदी की स्थिति, उसके महत्व और संरक्षण के उपायों की जानकारी दी जाए। जब समाज स्वयं अपनी नदी और जल स्रोतों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है, तब ऐसे प्रयास अधिक प्रभावी और स्थायी होते हैं।

मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि जल संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को सरल एवं सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि तकनीक तभी सार्थक है, जब उसका लाभ धरातल पर दिखाई दे और आम नागरिक उसे समझकर अपने जीवन में अपना सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों ने पीढ़ियों से मानव जीवन को जल, भोजन और आजीविका प्रदान की है। इसलिए एक सभ्य समाज के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नदियों और जल स्रोतों को सुरक्षित रखें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्रोत महोत्सव 2026 से निकलने वाले निष्कर्ष छत्तीसगढ़ में नदी संरक्षण और जल सुरक्षा की दिशा में एक प्रभावी रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

जल संरक्षण और आधुनिक तकनीक के लिए दो महत्वपूर्ण एमओयू

कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की संस्थागत और तकनीकी क्षमता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण एमओयू किए गए। नेशनल वाटर एकेडमी, पुणे के साथ हुए एमओयू के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और मैदानी अमले के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे आधुनिक जल प्रबंधन, नवीन तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, बेंगलुरु के साथ हुए एमओयू के माध्यम से इसरो की विशेषज्ञता और आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग जल संसाधनों के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निगरानी में किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में कुनकुरी तहसील के लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उन्नत भू-स्थानिक तकनीक के माध्यम से जल संसाधनों की स्थिति का अध्ययन, निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आधुनिक तकनीक से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों को स्थानीय अनुभव और पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़कर जल संरक्षण की अधिक प्रभावी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप समाधान तैयार करने और उनके परिणामों की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

नीर-नारी-निधि पुस्तक का विमोचन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में जल संरक्षण पर आधारित नीर-नारी-निधि पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक नीर की रक्षा, नारी की भागीदारी और जल संपदा के संरक्षण की अवधारणा को रेखांकित करती है। पुस्तक में जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न अनुभवों, प्रयासों और नवाचारों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

जलस्रोतों की पहचान और संरक्षण भविष्य की जल सुरक्षा के लिए जरूरी : डॉ. विनोद तारे

सीमेंगा के संस्थापक एवं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉ. विनोद तारे ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों के उद्गम और उन्हें पोषित करने वाले जल स्रोतों की पहचान एवं संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। बारिश का पानी ही नदियों और भू-जल का प्रमुख आधार है। वर्षाजल के तेज बहाव को नियंत्रित कर उसे अधिक से अधिक मात्रा में जमीन के भीतर पहुंचाना होगा, जिससे भू-जल स्तर बढ़े और भविष्य के लिए जल सुरक्षित किया जा सके। डॉ. तारे ने कहा कि जल संरक्षण के लिए प्राचीन ज्ञान, स्थानीय एवं पारंपरिक अनुभव और आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के बीच समन्वय जरूरी है। इन तीनों को एक साथ जोड़कर तैयार की गई कार्ययोजना ही जल स्रोतों के दीर्घकालिक संरक्षण और जल के सतत उपयोग का आधार बन सकती है।

साइंस बेस्ड और साइट स्पेसिफिक समाधान तैयार होंगे: जल संसाधन विभाग सचिव

जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने कहा कि स्रोत महोत्सव 2026 का उद्देश्य प्रदेश की नदियों के उद्गम और कैचमेंट एरिया के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक, व्यवहारिक और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करना है। नदी संरक्षण में केवल डाउनस्ट्रीम फ्लो का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सोर्स एरिया, भूमि उपयोग, मिट्टी की नमी, भू-जल रिचार्ज, वनस्पति और मृदा क्षरण सहित नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ समझना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में नौ नदी समूहों पर अलग-अलग चर्चा की जा रही है। इन समूहों में क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप साइट स्पेसिफिक और साइंस बेस्ड समाधान तैयार किए जाएंगे। इसमें समस्या की स्पष्ट पहचान के साथ समाधान, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी और परिणामों के आकलन की समय-सीमा भी निर्धारित करने पर जोर रहेगा।

श्री टोप्पो ने कहा कि जल संरक्षण केवल अधोसंरचना निर्माण का विषय नहीं है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी ही संरक्षण कार्यों की दीर्घकालिक सफलता और स्थायित्व की कुंजी है। कार्यशाला से प्राप्त सुझावों और निष्कर्षों के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए समयबद्ध रिवर सोर्स रेस्टोरेशन रोडमैप तैयार करने की दिशा में आगे कार्य किया जाएगा।

कार्यशाला में सीमेंगा के संस्थापक एवं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉ. विनोद तारे, नमामि गंगे मिशन से जुड़े विषय विशेषज्ञ, एनआईटी रायपुर के प्राध्यापक, राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य, विभिन्न जिलों के कलेक्टर एवं अधिकारी तथा जल एवं नदी संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ उपस्थित थे।

लोक निर्माण से छग निर्माण के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को दे रहे नई गति-अरुण साव

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य का सबसे बड़ा निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है। सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण के साथ विभागीय कार्यों में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए विभाग लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर-2023 में सरकार बनने के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता वीके

भतपहरी और अपर सचिव एसएन श्रीवास्तव भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रेस-कान्फ्रेंस में बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। इसमें सड़क निर्माण के 1285, पुलों के 247 और भवन निर्माण के 42 कार्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर-2023 से मार्च-2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किमी लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और दो भवन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के कुल 438 कार्यों के लिए की स्वीकृति दी गई। इनमें 1465 किमी लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इस वर्ष 9129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जो राज्य निर्माण के बाद पिछले 25 वर्षों के इतिहास में विभाग को मिली सर्वाधिक स्वीकृति है। इस वित्तीय वर्ष में 5129.60 किमी लंबाई की 754 सड़कों, 200 पुलों और 39 भवनों सहित कुल 993 कार्यों को मंजूरी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक विभाग को 608 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 608.20 किमी लंबाई की 59 सड़कें और दो पुलों के निर्माण शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग में कार्यों की गति बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया गया है। बेहतर संचालन और प्रशासनिक कसावट के लिए सात नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी और स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण भी शामिल है।

श्री साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही वेमिस (WAMIS - Work and Accounts Monitoring Integration System) लागू किया जाएगा। इस प्रणाली से डीपीआर तैयार करने से लेकर कार्य की स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन और एकीकृत प्रणाली से संचालित होंगी। इससे वर्तमान में विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले लंबे समय को कम किया जा सकेगा और निर्माण कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से विभागीय कामकाज में सुगमता के साथ गुणवत्ता और निगरानी में भी सुधार होगा। हम राज्य में लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को नई गति देने लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं।

संपादकीय

मांगें मानकर छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार

किसी भी देश में युवा व छात्र एक बड़ी ताकत होते हैं,वह जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो कोई भी सरकार हो देरसबेर उसे छात्रों की मांगों को मानना ही पड़ता है। छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ता है क्योंकि युवा व छात्रों की इतनी ताकत होती है कि वह किसी देश मे सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देने को विवश कर सकते हैं, अपने ही देश में अराजकता फैला सकते हैं ।अपने ही देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में युवाओं ने ऐसा किया है, इसलिए हमारे यहां के कुछ राजनीतिक दलों के नेता तो चाहते हैं कि इस देश के युवा भी देश मे अराजकता फैलाएं ।जंतर मंतर में युवाओं के आंदोलन के जरिए ऐसा करने का प्रयास शुरू किया गया लेकिन देशविरोधी ताकतों की साजिश को सरकार समझ गई और उसने युवाओं के विश्वास को जीतने का प्रयास शुरू किया और उसमें काफी हद तक वह सफल रही। शिक्षामंत्री को इस्तीफा देना पड़ा,इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, वह नहीं फैला सके। शुक्र है कि हमारे देश के युवा भी समझदार हैं और उन्होंने देशविरोधी ताकतों की साजिश को समझा और सरकार पर भरोसा किया और सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

देश में जंतर मंतर के आंदोलन की मांग शिक्षामंत्री के इस्तीफे की थी और केंद्र सरकार ने इस मांग को पूरा किया तो यह आंदोलन एक महीने में समाप्त हो गया। इस आंदोलन में परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग नहीं की गई थी, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कानून बनाई और भविष्य में तकनीकी सुधार के लिए एक टास्कफोर्स का गठन भी किया ताकि भविष्य मे नीट परीक्षा में कोई पेपर लीक न हो, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। जंतरमंतर का आंदोलन परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में था और वह एक ही मांग शिक्षामंत्री के इस्तीफे से समाप्त हो गया। इस आंदोलन के दौरान यदि संसद घेरने युवाओं का उपयोग नहीं किया गया होता यह आंदोलन भी एक अच्छे व प्रभावी आंदोलन में गिना जाता लेकिन पैसे देकर बुलाए गए बहुत से बाहरी लोगों की गाली, अश्लील भाषा, गंदे बैनर पोस्टर से जंतर मंतर के आंदोलन की आलोचना भी हुई है। बिहार के छात्रों ने इससे सबक लिया और अपनी तमाम मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आदोलन किया, विधानसभा का घेराव भी किया लेकिन उनकी उस तरह आलोचना नहीं हुई जितनी आलोचना जंतर मंतर के आंदोलन की हुई। झारखंड के छात्रों ने देश के छात्रों के सामने एक उदाहरण रखा है कि छात्र और युवा यदि शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो कोई भी सरकार हो उसको झुकना पड़ता है।

हर सरकार की तरह झारखंड सरकार ने 24 दिन तक कई तरह आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रयास किए,कभी कहा कि छात्रों की सारी मांगे नहीं मानी जा सकती,कभी बातचीत के जरिए मनाने का प्रयास किया,कभी टेंट न लगाने देकर उनकी परेशानी बढाई,कभी उसे भाजपा का आंदोलन कहा गया,कभी बाहरी लोगों को भेजकर आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया गया,बिधानसभा घेरने पर छात्रों के खिलाफ ढेर सारी एफआईआर दर्ज की गई, छात्रों को तिरंगा रैली नहीं निकालने दिया लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे तो आखिर में जाकर 24 दिन बाद सरकार ने एक मांग को छोड़कर सारी मांगे मानने का फैसला किया और झारखंड के छात्रों का आंदोलन इस तरह समाप्त हो गया है तो यह एक राज्य नहीं देश के छात्रों की जीत है और उनके लिए संदेश है कि देश में या राज्य में युवाओं का आंदोलन इसी तरह होना चाहिए ।इससे देश को नुकसान पहुंचाए बिना भी छात्र अपनी मा्ंगे पूरी करवा सकते हैं।

छात्रों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन मीडिया को बताया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं का संचालन करने वाली विवादित एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं की जांच झारखंड उच्च न्यायालय के रिटायर जज की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी करेगी। इतना ही नहीं झारखंड में 2014 के बाद हुई अन्य परीक्षाएं भी जांच के दायरे में रहेंगी ।जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश की नजर झारखंड के आंदोलन पर थी और सबको इंतजार था कि इनकी मांग सरकार कब पूरा करेगी। जंतर मंतर व झारखंड के युवाओं के आंदोलन से चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारे अब युवाओं की समस्याओं को लेकर सजग हो गई है और उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही हैं ताकि किसी राज्य में युवा आंदोलन न शुरू कर दें। खासकर उन राज्यों में जहां इस साल के आखिरी में या अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं के आंदोलन से बहुत खुश हैं। वह देश के कई खासकर भाजपा शासित राज्यों में युवाओं को अपने और कांग्रेस से जोड़ने के लिए गूंज कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं ।वह सोचते हैं कि युवाओं में जो नाराजगी किसी भी कारण से है, उसे मोदी की तरफ मोड़ देने से युवाओं का भरोसा उन पर और कांग्रेस पर बढ़ जाएगा और इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा ।राहुल गांधी सोचते हैं कि वह देश के युवाओं की मात्र तारीफ करेंगे तो युवा उनको अपना नेता मान लेंगे यही वजह है कि वह आए दिन कहते रहते हैं कि पीएम मोदी के हिंसक शासन के खिलाफ मजबूती के खड़े होकर जवाबदेही की मांग करने वाले भारत के युवाओं का साहस और दृढ़ता सराहनीय है ।वह भूल जाते हैं कि मोदी ने तो कह दिया है बता दिया है कि वह युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं लेकिन राहुल गांधी ने अब तक कई गूंज कार्यक्रम के बाद भी नहीं बताया है कि वह युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं। ऐसे में युवा राहुल गांधी पर भरोसा करें तो कैसे करें। उन्हें तो पता नहीं है कि राहुल गांधी की सरकार कब बनेगी,राहुल गांधी कब पीएम बनेंगे। जबकि युवाओं को मालूम है कि भाजपा अगला चुनाव जीती तो पीएम मोदी ही रहेंगे इसलिए वह उनकी वर्तमान व भविष्य की मांगे पूरी कर सकते हैं ।उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

अमेरिका में अब चलेगा इंडिया इलेक्शन मॉडल?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनावी व्यवस्था को लेकर देश के भीतर भले ही चुनाव-दर-चुनाव राजनीतिक बहस,आरोप-प्रत्यारोप और चुनाव आयोग कीकार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हों,लेकिन 18 अगस्त 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली और विशेष रूप से मतदाता पहचान व्यवस्था की सार्वजनिक प्रशंसा ने एक बिल्कुल अलग अंतरराष्ट्रीय तस्वीर सामने रख दी है ।उन्होंने 2024 के भारतीय लोकसभा चुनाव में लगभग 64 .6 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी का उदाहरण देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ।ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए अमेरिका में चुनाव सुधारों के लिए सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट यानी सेव एक्ट को आगे बढ़ाने की अपील की। ट्रंप ने भारत के विशाल चुनावी पैमाने का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब भारत इतनी बड़ी आबादी और करोड़ों मतदाताओं के साथ पहचान-आधारित चुनाव करा सकता है, तो अमेरिका में मतदाता पहचान को लेकर अधिक सख्त और एकसमान व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती ।भारत की चुनावी विशालता अमेरिका के लिए मिसाल बन गई है,भारत का चुनाव मॉडल इसलिए असाधारण है क्योंकि यहां चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विशाल भौगोलिक, भाषाई,सामाजिक और जनसंख्या विविधता के बीच संवैधानिक लोकतंत्र को संचालित करने का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभ्यास है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सात चरणों में मतदान कराया गया था।

साथियों, निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए ईपीआईसी यानी वोटर आईडी के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड,आधार सहित कई निर्धारित फोटो पहचान दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। यानी भारत में मूल सिद्धांत यह है कि मतदाता की पहचान मतदान केंद्र पर सत्यापित होनी चाहिए, हालांकि यह समझना जरूरी है कि केवल वोटर आईडी ही एकमात्र स्वीकार्य दस्तावेज नहीं है ।यही वह बिंदु है जिसने अमेरिकी राजनीतिक बहस को भारत की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है। ट्रंप ने 18 अगस्त की सुबह अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि इस महीने की शुरूआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया था कि अमेरिका वैध फोटो पहचान के बिना चुनाव कैसे कराता है। ट्रंप ने भारत के पिछले आम चुनाव का उल्लेख करते हुए लगभग 64 .6 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा सामने रखा और कहा कि एक प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक के जरिए मतदान किया तथा प्रत्येक मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज था। इसी तुलना को आधार बनाकर उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से सेव एक्ट पारित करने की मांग की।

साथियों बात अगर हम भारत और अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इसको समझने की करें तो, भारत और अमेरिका दोनों विश्व के महत्वपूर्ण लोकतंत्र हैं, लेकिन उनकी चुनावी संरचना एक जैसी नहीं हैभारत में चुनावों के संचालन के लिए एक केंद्रीयसंवैधानिक संस्था,निर्वाचन आयोग,की प्रमुख भूमिका है, जबकि अमेरिका में चुनावों का प्रशासन काफी हद तक राज्यों और स्थानीय चुनावी संस्थाओं के हाथ में है। यही कारण है कि अमेरिका में मतदाता पंजीकरण, पहचान संबंधी नियम,अर्ली वोटिंग एब्सेंटी वोटिंग और मेल झ्र इन वोटिंग जैसी व्यवस्थाओं में राज्य-दर-राज्य अंतर दिखाई देता है ।इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि अमेरिका में कोई एक समान राष्ट्रीय मतदान प्रक्रिया नहीं है, जबकि भारत में चुनाव संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अधिक केंद्रीकृत संवैधानिक ढांचा मौजूद है।

भारत में मतदाता पंजीकरण के बाद मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान की जांच होती है। दूसरी ओर, अमेरिका में संघीय चुनावों के लिए पहचान और नागरिकता संबंधी नियमों का ढांचा अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है। यही अंतर ट्रंप के सेव एक्ट अभियान का मूल राजनीतिक मुद्दा बन गया है। व्हाइट हाउस स्वयं दावा करता है कि भारत और ब्राजील जैसे देश मतदाता पहचान को अधिक मजबूत पहचान- प्रणालियों से जोड़ते हैं, जबकि अमेरिका में नागरिकता के संबंध में व्यापक रूप से सेल्फ- अटेस्टेशन कीव्यवस्था पर निर्भरता रही है। हालांकि इस तुलना को सावधानी से समझना जरूरी है,भारत में भी आधार को अनिवार्य मतदाता पहचान के रूप में इस्तेमाल करने का अर्थ नहीं है; निर्वाचन आयोग मतदान के लिए कई वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज स्वीकार करता है।

साथियों बात अगर हम क्या है सेव अमेरिका एक्ट ?इसको समझने की करें तो,यहां एक महत्वपूर्णतथ्यात्मक स्पष्टता आवश्यक है। इसका आधिकारिक नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट , संक्षेप में सेव एक्ट है। यह कोई स्वास्थ्य संबंधी सेव कानून नहीं, बल्कि अमेरिकी चुनावों में मतदाता पात्रता और नागरिकता सत्यापन से जुड़ा प्रस्तावित संघीय कानून है। इसका मूल उद्देश्य संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करना है। आधिकारिक विधायी रिकॉर्ड के अनुसार एच .आर .22 को 3 जनवरी 2025 को प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया और 10 अप्रैल 2025 को सदन ने इसे 220-208 मतों से पारित कर दिया। इसके बाद यह सीनेट को भेजा गया। इसलिए इसे यह कहना सही नहीं होगा कि सेव एक्ट पहले ही पूर्ण संघीय कानून बन चुका है ।प्रस्तावित कानून में अमेरिकी नागरिकता साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की व्यवस्था की गई है, जिनमें वैध अमेरिकी पासपोर्ट, कुछ प्रकार के रियल आईडी -अनुरूप पहचान दस्तावेज, सैन्य पहचान एवं संबंधित रिकॉर्ड तथा सरकार द्वारा जारी कुछ अन्य दस्तावेज शामिल हैं। कानून का मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संघीय चुनावों में केवल पात्र अमेरिकी नागरिक ही पंजीकृत हों।

साथियों बात अगर हम मेल-इन वोटिंग पर भी सख्ती का प्रस्ताव को समझने की करें तो,सेव एक्ट की बहस केवल फोटो पहचान तक सीमित नहीं है। व्हाइट हाउस के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में सामान्य मेल-इन बल्लोंट्स को सीमित करने और बीमारी, विकलांगता,सैन्य सेवा अथवा यात्रा जैसे विशेष मामलों में उन्हें अनुमति देने का प्रस्ताव है। साथ ही राज्यों को मतदाता सूचियों से गैर- नागरिकों के नाम हटाने के लिए व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई है ।यहीं से अमेरिका की चुनावी बहस अधिक संवेदनशील हो जाती है। समर्थकों का तर्क है कि मतदान प्रक्रिया में नागरिकता और पहचान की मजबूत पुष्टि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाएगी। विरोधियों की चिंता है कि अत्यधिक दस्तावेजी बाध्यताएं उन वैध मतदाताओं के लिए मतदान कठिन कर सकती हैं जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अमेरिकी बहस का वास्तविक प्रश्न केवल यह नहीं है कि वोटर आईडी होना चाहिए या नहीं? बल्कि यह है कि पहचान और नागरिकता सत्यापन की व्यवस्था ऐसी कैसे हो जो चुनावी सुरक्षा भी बढ़ाए और पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार में अनावश्यक बाधा भी न डाले।

साथियों बात अगर हम ट्रंप का अमेरिक ी फर्स्ट अब इंडिया इलेक्शन मॉडल से जुड़ता दिखाई दे रहा है,ट्रंप लंबे समय से अमेरिक ी फर्स्ट की राजनीति केसमर्थक रहे हैं। लेकिन इस बार उनके चुनावी सुधार अभियान में भारत का उदाहरण सामने आना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस भारत की चुनावी प्रणाली को लेकर भारतीय राजनीति में लगातार बहस होती रहती है, उसी व्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश में चुनावी सुधारों के पक्ष में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यहअत : अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना अमेरिकी चुनावी बहस का संदर्भ 18 अगस्त 2026 की ट्रंप टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत-अमेरिका संबंधों की चर्चा को व्यापार,रक्षा,तकनीक और रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्थाओं तक पहुंचा दिया है। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कथित सवाल का हवाला देकर अपने सेव एक्टअभियान को मजबूत करने की कोशिश की है और भारत के विशाल चुनावी अनुभव को अमेरिकी मतदाता पहचान बहस के केंद्र में ला दिया है ।लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से कुछ सीखने की बात करे ।आज सवाल केवल यह नहीं है कि अमेरिका भारत से क्या सीखेगा ;बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी इस अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा को आत्ममुग्धता के बजाय अपनी चुनावी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के अवसर में बदलेगा? यही वह बिंदु है जहां अमेरिक ी फर्स्ट की बहस में भारत का चुनावी मॉडल एक नई कड़ी जोड़ता दिखाई देता है डेमोक्रेसी फर्स्ट ,वोटर फर्स्ट और ट्रस्ट फर्स्ट। भारतीय लोकतंत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उल्लेखनीय क्षण है ।यहां एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाई देता है। भारत में प्रत्येक बड़े चुनाव के बादईवीएम मतदाता सूची, चुनाव आयोग की निष्पक्षता मतदान प्रतिशत और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद उठते हैं। विपक्ष कई बार चुनाव आयोग से सवाल करता है और सत्ता पक्ष चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता का बचाव करता है। लेकिन उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत की मतदाता पहचान व्यवस्था को अमेरिकी चुनाव सुधार के संदर्भ में उद्धृत किया जाना यह संकेत देता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन केवल घरेलू राजनीतिक चश्मे से सटीकता से नहीं किया जाना चाहिए।

साथियों बात अगर हम भारत के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है इसको समझने की करें तो,ट्रंप की टिप्पणी को केवल भारत की प्रशंसा मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा ।यह भारत के लिए भी आत्ममंथन का अवसर है। यदि विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश भारत की चुनावी पहचान प्रणाली से कोई तत्व सीखने योग्य मानता है,तो भारत को भी अपनी चुनावी व्यवस्था को लगातार अधिक पारदर्शी तकनीकी रूप से सुरक्षित और राजनीतिक रूप से विश्वसनीय बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ।किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत केवल इस बात में नहीं होती किचुनाव समय पर हो जाए; असली ताकत तब होती है जब मतदाता को विश्वास हो कि उसका नाम सही है, उसकी पहचान सुरक्षित है, उसका वोट सही तरीके से दर्ज हुआ है और परिणाम निष्पक्ष प्रक्रिया से निकला है। भारत ने दुनिया को सबसे बड़े पैमाने पर चुनाव कराने की क्षमता दिखाई है। अब अगली चुनौती इस क्षमता के साथ विश्वास की गहराई बढ़ाने की है।

"#ActForHumanity"- करुणा और कर्तव्य का पुनर्जागरण

वंदना चौधरी, भिलाई

मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है। — स्वामी विवेकानंद यह वाक्य आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब दुनिया विभाजन, हिंसा और असमानताओं से जूझ रही है, तब करुणा और सहयोग ही वह शक्ति है जो मानवता को जीवित रख सकती है। विश्व मानवतावादी दिवस (19 अगस्त) उन निस्वार्थ कार्यकताओं के साहस और समर्पण को सम्मानित करने का अवसर है, जिन्होंने संकटग्रस्त परिस्थितियों में मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

2003 में बगदाद स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो भी शामिल थे। डी मेलो का जीवन मानवाधिकारों की रक्षा और शांति स्थापना के लिए समर्पित था। उनका बलिदान इस बात का प्रतीक है कि मानवता की सेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक तपस्या है। इसी घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस घोषित किया।

मानवतावादी कार्यकताओं की भूमिका

मानवतावादी कार्यकर्ता उन परिस्थितियों में कार्य करते हैं जहाँ जीवन का अस्तित्व ही संकट में होता है। वे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में घायल और विस्थापित लोगों को आश्रय देते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुँचाते हैं, और गरीबी से जूझते समाजों में शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं। उनका उद्देश्य केवल तत्काल सहायता देना नहीं, बल्कि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना होता है। उनका कार्य हमें यह सिखाता है कि मानवता की सेवा सीमाओं से परे है—यह न जाति देखती है, न धर्म, न भाषा।

आज का वैश्विक परिप्रेक्ष्य

21वीं सदी का यह युग तकनीकी प्रगति के साथ-साथ मानवीय संकटों का भी युग है। जलवायु परिवर्तन ने बाढ़, सूखा और तूफान जैसी आपदाओं को बढ़ा दिया है। युद्ध और आतंकवाद ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। महामारी और स्वास्थ्य संकटों ने वैश्विक असमानताओं को उजागर किया है। इन परिस्थितियों में मानवतावादी कार्यकताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे न केवल राहत पहुँचाते हैं, बल्कि समाज को यह संदेश भी देते हैं कि करुणा और सहयोग ही मानवता की असली शक्ति है।

भारत का दृष्टिकोण

भारत की परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम् — संपूर्ण विश्व एक परिवार है — इस दिवस के मूल भाव को सार्थक करती है। भारत में भी मानवतावादी भावना गहराई से रची-बसी है। कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और स्वयंसेवकों ने जिस साहस और समर्पण से कार्य किया, वह मानवतावाद का जीवंत उदाहरण है। बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों में जुटे स्वयंसेवक समाज की रीढ़ बन जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए कार्यरत संगठन मानवता की सेवा को व्यवहार में उतार रहे हैं।

इस वर्ष का वैश्विक थीम

2026 का आह्वान है - "#ActForHumanity"। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि हम सब मिलकर मानवता की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाएँ। हमें विशेष ध्यान देना चाहिए : Families of Fallen Humanitarians – उन aid workers के परिवारों सदस्यों का जिनकी कहानियाँ और अनुभवों को सामने लाना जिन्होंने सेवा करते हुए अपने प्रियजनों को खोया।

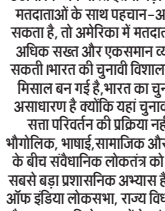

संदेश: हिंसा और बाधाओं को रोकें। हर हमले की

जाँच करें और दोषियों को दंडित करें। पीड़ितों और उनके परिवारों को सहयोग दें। चेतावनी संकेतों को अनदेखा न करें, समय रहते कार्रवाई करें।

चुनौतियाँ और जोखिम

मानवतावादी कार्यकताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फिर भी उनका समर्पण अडिग रहता है। युद्ध क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। संसाधनों की कमी उनके कार्य को सीमित करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएँ उनके प्रयासों को प्रभावित करती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विश्व मानवतावादी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मानवता की सेवा केवल कुछ चुनिंदा लोगों का कार्य नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यदि हम अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें, तो हम भी इस परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं। करुणा, सहयोग और साहस को अपने जीवन में उतारना ही इस दिवस का वास्तविक उद्देश्य है। आज जब दुनिया विभाजन, हिंसा और असमानताओं से जूझ रही है, तब यह दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है—क्या हम अपने भीतर की मानवता को जीवित रख पा रहे हैं?

रूस-यूक्रेन युद्ध : मानवीय संकट की गहराई

2022 से जारी रूसझ्रयूक्रेन युद्ध ने यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा किया है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए, बच्चों और बुजुर्गों को सीमाओं के पार शरण लेनी पड़ी। अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढाँचे के विनाश ने मानवीय कार्यकताओं को सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश किया।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव

2025 का बारह दिन का युद्ध : इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए। इस संघर्ष ने मध्य-पूर्व को अस्थिर कर दिया और लाखों नागरिकों को विस्थापित किया।

2026 की घटनाएँ : हाल ही में अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मृत्यु ने तनाव को और गहरा कर दिया है। इस घटना ने मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है—स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित हुई, शरणार्थियों की संख्या बढ़ी और आम जनता भय और असुरक्षा में जी रही है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक और सामरिक संघर्षों का सबसे बड़ा बोझ आम नागरिकों पर पड़ता है।

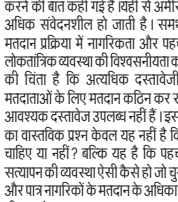

विश्व मानवतावादी दिवस 2026 का थीम "#ActForHumanity" हमें यह याद दिलाता है कि मानवता की रक्षा और सेवा में सक्रिय होना ही हमारा कर्तव्य है। यह दिवस उन कार्यकताओं के बलिदान को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने संकटग्रस्त लोगों की सहायता करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मानवता की रक्षा और सेवा में सदैव सक्रिय रहेंगे, और aid workers के साहस तथा बलिदान को अपनी प्रेरणा बनाएँगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है। मानवता के प्रहरी हमें यह सिखाते हैं कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने स्तर पर मानवीय मूल्यों की रक्षा करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कविता का कोना

उम्मीदों के पंख लगाकर

उम्मीदों के पंख लगाकर
हमने उड़ना सीखा है
हर सपनों को सच कर जाए
ऐसा हमने सोचा है।

हो कोई भी कठिनाइयाँ
या कोई विपदा का सामना
अपने सपनों को पूरा करेंगे
ऐसा हमने सोचा है।

कभी कोई खुशी हो
यह हो कोई गम का दौर
हम तो आगे बढ़ते जाएँगे
ऐसा हमने सोचा है।

इम्तहान हो कोई चाहे
या हो कोई खेल का मैदान
हम फतह हासिल करेंगे
ऐसा हमने सोचा है।

उम्मीदों के पंख लगाकर
ऊँची उड़ान भरना है
हर मंजिल को तय कर
हमको आगे बढ़ना है।

गीता जुन्जानी
दिल्ली पब्लिक स्कूल, भिलाई
हेडमिस्ट्रेस, जूनियर विंग

कविता का कोना

क्यों इतनी चालाकी

क्यों इतनी चालाकी करके,
दूसरे का अपमान किया,
अपनी मतलब की खातिर तुमने,
मासूम दिल को तार-तार किया।

भरोसे की तुमने ना परवाह की,
हमने समझा तुमको अपना,
तुमने तो उस विश्वास को,
बना दिया एक अधूरा सपना।

अरमानों को हमारे तुमने,
कांच का टुकड़ा बना दिया,
जिस दिल ने तुम पर भरोसा किया,
उसी दिल को तुमने दुखा दिया।

क्यों इतनी चालाकी करके,
दूसरे का अपमान किया,
अपनी मतलब की खातिर तुमने,
मासूम दिल को तार-तार किया।

कवियत्री-
ममता दुबे भिलाई

कविता का कोना

महासागर

अथाह नीलाई, रहस्यमयी उसका
रूप,
लहरों के गीतों में छिपा अनंत
स्वरूप।

कभी शांत, कभी प्रचंड उफान,
प्रकृति की शक्ति का वह जीवंत
प्रमाण।

किनारों को छूकर देता नया संदेश,
धैर्य, संयम और आशा का अनमोल
उपदेश।

महासागर विशाल, मन को दे नई
उड़ान,
उसकी गहराइयों में छिपी है सृष्टि की
महान पहचान।

मृदुला रोजिंदार, भिलाई -छ.ग.

नौकरी की मजबूरी

भारतीय नाविकों के सामने भी नौकरी की मजबूरी है, जिससे जहाज मालिकों का निर्देश मानने के लिए वे विवश बने हुए हैं। जबकि फारस की खाड़ी, लाल सागर, और काला सागर में जोखिम बढ़ता जा रहा है।

लाल सागर में यमन के पास भारतीय झंडे वाला एक व्यावसायिक जहाज डूब गया। राहत की बात है कि जहाज पर सवार 14 नाविकों को बचा लिया गया, जिनमें 13 भारतीय हैं। भारतीय जहाज एसएसवी फैज नूर ओलिया पर यमन के हुदैदा/ मोखा बंदरगाह के पास मिसाइल अथवा ड्रोन से हमला हुआ। हमला किसने किया, तुरंत यह मालूम नहीं हो सका, लेकिन यमन के पास इस जलमार्ग में जहाजों को अक्सर अंसारुल्लाह (हुती) विद्रोही निशाना बनाते रहे हैं। अंसारुल्लाह ने लाल सागर में मौजूद बाब-ए-मंदाब जल मार्ग को आम नौवहन के लिए बंद कर रखा है। इसके पहले खाड़ी में पांच महीनों से जारी युद्ध के दौरान होरमुज जलडमरूमध्य के आसपास जहाजों पर हुए हमलों में कम-से-कम 14 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं।

इस बीच पिछले महीने काला सागर से गुजरने का प्रयास भी भारतीय नाविकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। बीते 18 जुलाई और 19 जुलाई को दो हमलों में पांच भारतीय नाविक मारे गए। ये हमले यूक्रेन ने किए। ऐसे मामलों में भारत सरकार की प्रतिक्रिया "कड़ी निंदा" करने तक सीमित रही है। पिछले महीने यह खबर जरूर मीडिया में आई थी कि भारत सरकार ने शिपिंग कंपनियों को खतरनाक इलाकों में जाने वाले

जहाजों में भारतीय नाविकों की ड्यूटी ना लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे कथित निर्देश के औचित्य पर तभी कई सवाल उठे थे। बहरहाल, अब यह साफ हो चुका है कि अगर सचमुच वैसा कोई दिशा-निर्देश दिया गया था, तो वह बेअसर साबित हुआ है।

तमाम नाविकों की तरह भारतीय नाविकों के सामने भी नौकरी की मजबूरी है, जिससे जहाज मालिकों का निर्देश मानने के लिए वे विवश हैं। जबकि फारस की खाड़ी, लाल सागर, और काला सागर में जोखिम बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब सबसे बड़ा मसला होरमुज का ही रह गया है, जिस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ईरान अडिग है। उधर हूतियों और सऊदी अरब के बीच लड़ाई छिड़ने से लाल सागर में भी खतरा बढ़ा है। इन सबके बीच भारतीय नाविकों को कैसे बचाया जाए, यह सवाल रोज अधिक बड़ा होता चला गया है।

क्या स्त्रियों को आजादी मिल पाई है मानसिक गुलामी से?

साप्ताहिक जलसा — स्वयंसिद्धा

छत्तीसगढ़ की अग्रणी महिला संस्था स्वयंसिद्धा-ए मिशन विद ए विजन द्वारा गत 7 वर्षों से प्रत्येक सप्ताह संगीत, साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य, सिनेमा, फोटोग्राफी, कानूनी सलाह आदि समसामयिक विषयों पर नियमित स्तंभ चलाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक मंगलवार परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

अधिकारियों, जिम्मेदारों, नेताओं, मंत्रियों के विचार तो हम हमेशा सुनते हैं लेकिन आम गृहणियां और माताएं समसामयिक विषयों पर क्या सोचती है इस पर हमने कभी बात नहीं की।

परिचर्चा का शुभारंभ करते हुए संस्था प्रमुख डॉ.सोनाली चक्रवर्ती ने कहा-"हमें आजादी अंग्रेजों से तो मिल गई लेकिन अब कई समस्याओं से चाहिए। 80 वर्ष हो गए स्वतंत्र भारत बने लेकिन उसके बाद हम कई बंधनों में उलझ कर रह गए। अशिक्षा, रूढ़िवादी परंपराएं अंधविश्वास, स्त्रियों के प्रति निकृष्ट सोच आदि कई बंधनों में हमारा देश अभी भी जकड़ा हुआ है। इन सबसे छुटकारा पाने के बाद ही हम असली आजादी को महसूस कर पाएंगे।"

देबजानी मजूमदार ने कहा -"80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमें सिर्फ.बंधनों से नहीं सोच की बेड़ियों से भी आजादी चाहिए। हमें संकीर्ण मानसिकता से आजादी चाहिए एक-दूसरे पर कटाक्ष करने की आदत से आजादी चाहिए, औरत होने की वजह से होने वाले भेदभाव और दुर्व्यवहार से आजादी चाहिए, हमें डर से, दिखावे से, असमानता से और चुप रहने की मजबूरी से आजादी चाहिए।कितना चुप रहेंगे? 'बोलने से ही अशांति होगी इसलिए चुप रहती हूँ' इस सोच से आजादी चाहिए। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी आजादी माँगें जहाँ हर इंसान को सम्मान से जीने का हक मिले।अकेले आने जाने में जो डर लगता है उससे आजादी चाहिए।

धमतरी निवासी संतोष लखोटिया कहती है-"हमें आजादी तो चाहिये लेकिन उसके लिये पहल तो करना ही पड़ेगा। लोग महिलाओ के साथ अभ्रदता एवं गाली से क्यों बात करते हैं क्या वो कमजोर है? - नहीं वे कमजोर नहीं है नारी की शक्ति (दुर्गा) को पहचानने में भूल की है जब वे जाग जाय तो फिर किसी की खैर नहीं।और भी कई कारण है। जातिवाद, आर्थिक विषमता, हर क्षेत्र में बेटा - बेटी में भेद भाव ओर अशिक्षा। इन सब को पीछे धकेलकर हम सब एकजुट होकर भारत को उन्नति शील बनाना है । सबके प्रति समान भाव दुखों का निवारण है। मैं तो कहती हूँ तिरंगे की कसम खाकर सबको प्रण करना चाहिये मै किसी भी अच्छे कार्य में बाधक नही हूँ और अपने अपने कर्तव्यों का सही तरीकों से पालन करके ये उपरोक्त सारी कमिया दूर करेंगें तभी भारतीय सच में बनेंगें।

स्मृति नगर निवासी अनामिका कपूर कहती है-"आज हमें सबसे पहले संकीर्ण मानसिकता और आपसी नफरत से आजादी चाहिए ।यही वह एक चीज हैं जो हमारे देश के सामाजिक सौहार्द और प्रगति की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं ।जब तक विचार आजाद और एकजुट नहीं होंगे, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी है।

मॉडल टाउन निवासी नमिता त्रिपाठी कहती है-"सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं, हाथ बांधकर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाते हैं, मिठाई बांटते हैं और देशभक्ति की बातें करते हैं यही भावना पूरे साल रहे तो सच्ची स्वतंत्रता है।

अवधपुरी निवासी रतना दुफारे का कहना हैं -"आजादी के 80 वर्ष में अब हमें एक चीज से आजादी चाहिए वह है महिलाओं में हिंसा और असमानता। आजादी के इतने साल बाद भी संपूर्ण भारत में महिलाएं आज भी मानसिक तौर पर गुलाम है।अंधविश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर दिया जाता है।आज भी वही पुरानी सोच पर महिलाएं चल रही है। वैचारिक आजादी चाहिए जब महिलाएं अपने से सोच सके, अपने निर्णय खुद ले सके, खुद को किसी से कम ना समझे। अपने अस्तित्व पर गर्व कर सके,

दहेज के लिए कितनी महिलाओं की हत्या होती रही है। छोटी-छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिला तक कोई सुरक्षित नहीं है। मानसिक उत्पीड़न बहुत सी महिलाएं सहती है जहां शरीर पर कोई घाव नहीं दिखाई देता पर मन छलनी हो जाता है महिलाओं के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग से। हम महिलाओं को इन अत्याचारों और असमानता से आजादी चाहिए।

महिला उद्यमी विनीत गुप्ता कहती है -"बहुत विचारणीय प्रश्न है कि आजादी के 80 वे वर्ष में हमें किस एक चीज से आजादी चाहिये ।आज के युग में जब महिलाएं समान अधिकारी की श्रेणी में प्रवेश कर चुकी हैं, आज जब हम पुरुष प्रधान समाज में अपना स्थायित्व जमा चुके तो क्यों नहीं हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ उसे भी आगे लाएं ' शायद तभी हम समाज को देश को बहुत जल्दी नयी दिशा मे आगे बढ़ा पाएंगे।

जयपुर निवासी फिटनेस कोच ललिता नाहटा कहती है-' आजादी के 80वें वर्ष में केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि उन आदतों और सोच से भी आजादी की जरूरत है जो देश की प्रगति में बाधा बनती हैं।

1- हमें आजादी चाहिए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से।

2-महिलाओं के प्रति असमानता और असुरक्षा से।

3-अभद्र भाषा और गाली गलौज जो की मां बहनों के नाम पर इस्तेमाल की जाती है।

4-स्वार्थ, हिंसा और नफरत की भावना से।

5- मैं की भावना को छोड़कर हम की भावना के साथ आगे बढ़ने की।

6-इस प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हर आदत से ।सच्ची आजादी तभी होगी जब हम सब जिम्मेदार, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनेंगे।

सेक्टर 4 निवासी शशि किरण पटेल कहती है -" आजादी के 80 वर्ष तो हो गए पर अभद्र भाषा से आजादी भी चाहिए। आज के बच्चे खूब गाली गलौज देते हैं उनको समझाना होगा।

खास खबर

सहकारी समितियों का कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किया दौरा, धान भंडारण व्यवस्था का लिया जायजा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निदेर्शानुसार प्रदेश में धान उपार्जन एवं संग्रहण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति, किसानों के हितों तथा धान के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की निगरानी के उद्देश्य से जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने आज अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के सेवा सहकारी समितियों सोमनी, नन्दौरी, मुरमुंदा एवं नारधा का दौरा कर धान संग्रहण एवं भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने संबंधित समितियों में संग्रहित धान की स्थिति का जायजा लिया तथा धान के सुरक्षित रख-रखाव, परिवहन एवं उठाव की वर्तमान स्थिति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से जानकारी ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निदेर्शानुसार संग्रहण केंद्रों में कुल भंडारित धान, धान के उठाव एवं परिवहन की स्थिति तथा वर्तमान में रखे धान की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने विशेष रूप से यह भी जानकारी ली कि बारिश एवं नमी के कारण कहीं धान के खराब होने अथवा रख-रखाव में किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हो रही है। निरीक्षण के दौरान संग्रहण केंद्रों की वास्तविक स्थिति की फोटो एवं वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

किसानों से की चर्चा, खाद की उपलब्धता को लेकर सामने आई समस्या

दौरे के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किसानों से भी सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों ने बताया कि वर्तमान में धान की खेती के लिए सबसे आवश्यक डीएपी खाद की सोसायटियों में पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, किसानों को सरकार खाद तो उपलब्ध नही करा पा रहा है लेकिन खाद की कालाबाजारी जोरों पर है जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की इस समस्या पर राकेश ठाकुर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर सरकार किसानों की आय और कृषि व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को खेती के महत्वपूर्ण समय में आवश्यक खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देते हुए सोसायटियों में तत्काल पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराना चाहिए।

कोरोना काल में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी : राकेश ठाकुर

राकेश ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी और किसानों को खाद की समस्या नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि उस समय पूरे देश में कठिन परिस्थितियां थीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान खाद के लिए सोसायटियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। यह स्थिति सरकार के किसान हितैषी होने के दावों पर सवाल खड़े करती है। किसानों को समय पर खाद, बीज और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

राकेश ठाकुर ने कहा कि किसानों की मेहनत से उपार्जित धान का सुरक्षित भंडारण एवं समय पर उठाव सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। संग्रहण केंद्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण धान को नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने समिति प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों से बारिश और नमी से धान को सुरक्षित रखने तथा समय पर उठाव एवं परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों और जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर लगातार जमीनी स्तर पर निगरानी रख रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल राजनीतिक विरोध करना नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत की उपज सुरक्षित रहे, उन्हें समय पर खाद मिले और खेती-किसानी में किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर निगरानी रखना है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य धान संग्रहण केंद्रों एवं सेवा सहकारी समितियों का भी निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इस दौरान प्रमोद राजपूत, हीरा वर्मा, प्रकाश ठाकुर, उमेश साहू, श्रीकांत वर्मा, कमलेश साहू, आकाश कुर्रे, अभिषेक जांगड़े, जगदीश मारकंडे, पंकज सिकट, धरम बर्रे, सुमित नारंग, सुमन साहू, गज्जू साहू, सुनीता चन्नेवार, रामप्यारी वर्मा, रानी बंछोर, मोहन साहू, पप्पू गोपेन्द्र चंद्राकर, टेनेंद्र ठाकरे, सुयश शखरे, बबुआ, ओंकार निर्मलकर, इस्माईल आजाद, लेख राम साहू, चन्द्र शेखर शर्मा, योगेश टिकरिहा, भोज पाटिल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन एवं किसान मौजूद रहे।

---

8 दिव्यांगजनों को विधायक ललित चंद्राकर ने वितरित किए ट्राइसिकल और श्रवण यंत्र

विधायक बोले—सम्मान और सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर के निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पात्र दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राइसिकल, सामान्य ट्राइसिकल एवं श्रवण यंत्र (कान की मशीन) प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विधायक श्री चंद्राकर ने लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान करते हुए उनके सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों से दिव्यांगजनों को आवागमन, शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन के कार्यों में सुविधा मिलेगी तथा वे अधिक आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

कार्यक्रम में ग्राम डुडेरा के गोकुल कोसरे, ग्राम जंजगिरी के राजूलाल देशमुख, ग्राम खम्हरिया के हरिश कुमार साहू, ग्राम खोपली के पंकज कुमार कोसरे, ग्राम विनायकपुर के रामस्वरूप देशमुख, ग्राम करगाडीह के लुमेश कुमार साहू, ग्राम रुआबांधा रिसली गांधी चौक के सैमुएल छुरा एवं ग्राम झोला के रोहित निषाद को बैटरी चलित ट्राइसिकल, सामान्य ट्राइसिकल एवं श्रवण यंत्र प्रदान किए गए।

दिव्यांगजनों को समान अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी

विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि किसी भी संवेदनशील और विकसित समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और आगे बढ़ने का अधिकार मिले। दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी प्रतिभा, क्षमता और आत्मविश्वास को उचित अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनकर सम्मानपूर्वक समाज की मुख्यधारा में अपना योगदान दें।

ये उपकरण आपके सपनों की उड़ान के पंख हैं

लाभार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी दिव्यांगजन दूसरों पर निर्भर न रहे और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि ट्राइसिकल और श्रवण यंत्र केवल सहायक उपकरण नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के साधन हैं। उन्होंने लाभार्थियों से शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सहायक उपकरण वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण, कौशल विकास, पुनर्वास सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र दिव्यांगजन शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिला मंत्री नवीन पवार, उतई मंडल अध्यक्ष श्रीमती शीतला ठाकुर, रिसाली मंडल अध्यक्ष एकनाथ अनुपम साहू, मरोदा-पुरैना मंडल अध्यक्ष राजू राकेश जंघेल, अंडा-निकुम मंडल अध्यक्ष लिकेश्वर देशमुख, महामंत्री चंदू देवांगन, प्रवीण यदु, गुड्डू झा, पुनाराम कलिहारी, योगेश कुमार सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों एवं उनके परिजनों ने विधायक ललित चंद्राकर तथा राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सहायक उपकरण मिलने से उनके दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

पेंटर-चित्रकारों को भी मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में शामिल करने की मांग

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 में पेंटर एवं चित्रकार कलाकारों को भी शामिल किए जाने की मांग तेज हो गई है। वर्तमान में योजना में मूर्तिकार एवं शिल्पकारों को शामिल किए जाने तथा पेंटर-चित्रकारों को इससे वंचित रखे जाने पर प्रदेश के कलाकारों ने शासन-प्रशासन से समान अवसर देने की मांग की है।

कलाकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पेंटर, चित्रकार सहित विभिन्न कला विधाओं से जुड़े कलाकार वर्षों से अपनी कला के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे में प्रोत्साहन योजना में पेंटर एवं चित्रकारों को शामिल नहीं किया जाना उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है। कलाकारों के अनुसार योजना के अंतर्गत वर्तमान में मूर्तिकार एवं शिल्पकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित है। उनका कहना है कि इसी प्रकार पेंटर एवं चित्रकार कलाकारों को भी योजना की पात्रता में शामिल कर समान रूप से प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाना चाहिए।

इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ एवं छत्तीसगढ़ कलाकार सेवा समिति, दुर्ग के तत्वावधान में दुर्ग में कलाकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्कृति विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पेंटर एवं चित्रकार कलाकारों को मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में शामिल करने के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कलाकारों ने एकजुट होकर कहा कि कला की किसी भी विधा से जुड़े कलाकार के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेंटर एवं चित्रकार भी लोककला, संस्कृति और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए उन्हें भी शासन की कलाकार प्रोत्साहन योजना में समान अवसर मिलना चाहिए।

बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं संयोजक देवानंद साहू, अनुशासन समिति अध्यक्ष दीपक यादव, प्रदेश अध्यक्ष परम यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष बाबा सिन्हा, दुर्ग जिला अध्यक्ष प्रवीण वासनिक, दुर्ग संभागीय अध्यक्ष रवि गौर, राजनांदगांव संभागीय अध्यक्ष देवा रंगारी, समिति कोषाध्यक्ष विनय ताम्रकार, संरक्षक रमन, मीडिया प्रभारी महेश राव सहित प्रदेशभर से आए जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में सदस्य कलाकार उपस्थित रहे।

कलाकारों ने छत्तीसगढ़ शासन एवं संस्कृति विभाग से मांग की है कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में पेंटर एवं चित्रकारों को शीघ्र शामिल कर उन्हें भी समान रूप से प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाए। कलाकारों का कहना है कि इससे प्रदेश के सभी कला विधाओं से जुड़े कलाकारों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने का समान अवसर प्राप्त होगा।

बैठक — 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता की सख्त मॉनिटरिंग और ट्रामा सेंटरों को सुदृढ़ करने पर बल

मुख्य सचिव विकासशील ने दिए सड़क सुरक्षा उपायों के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों के तहत प्रदेश में किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। एनआईसी दुर्ग से कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ए.के. भटटाचार्य सहित अन्य जिला प्रमुख अधिकारी बैठक में जुड़े थे।

बैठक के मुख्य बिंदु और निर्देश

दुर्घटना में घायलों का इलाज प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता की सख्त मॉनिटरिंग और ट्रामा सेंटरों को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। सड़क दुर्घटना के घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले नेक नागरिकों (गुड सेमेरिटन) को यथाशीघ्र प्रोत्साहन एवं सम्मान राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

दुर्घटनाओं में कमी लाने सड़क निर्माण के पूर्व ही डिजाइन सही बनाएं

ब्लैक स्पॉट्स का सुधार एवं विश्लेषण के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को ब्लैक स्पॉट्स में समय-सीमा के भीतर सुधार करने और सुधार के बाद दुर्घटनाओं में आई कमी का विश्लेषण करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने जोर दिया कि बाद में सुधार करने से बेहतर है कि सड़कों की शुरूआती डिजाइन ही सही हो। सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

दुर्घटनाओं के कारणों का गहन विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार करने निर्देश

अधिक दुर्घटना वाले 8 जिलों पर विशेष फोकस किया गया, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा और जगदलपुर (बस्तर) जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों का गहन विश्लेषण कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों को यातायात जागरूकता से जोड़े

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में रोड क्लब गठित करने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सुगम यातायात प्रबंधन से जोड़ने पर जोर दिया गया, ताकि युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी बनी रहे। सभी जिलों के कलेक्टरों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक की शुरूआत में परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।

रानी मुखर्जी को मिला खास सम्मान, सिनेमा में पूरे किए 3 दशक

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक अलग-अलग किरदार निभाए हैं। उन्होंने कभी समाज की सोच को चुनौती देने वाली महिलाओं का किरदार निभाया, तो कभी मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाने वाली महिलाओं की कहानी पर्दे पर उतारी। अब इसी को देखते हुए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। तीन दशक से ज्यादा समय से अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली रानी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में खास सम्मान दिया गया है।

उन्हें एक्टिंग में बेहतरीन योगदान के लिए स्पेशल सिटेशन से सम्मानित किया गया। रानी के इस सम्मान को भारतीय सिनेमा में उनके लंबे और शानदार सफर के लिए एक बड़ी पहचान माना जा रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं। उनके किरदारों और फिल्मों ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी लोगों के दिलों तक जगह बनाई है।

तीन दशक में निभाए कई यादगार किरदार

'ब्लैक', 'हम तुम', 'युवा', 'बंटी और बबली', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'हिचकी', 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी और 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' जैसी फिल्मों में रानी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। रानी ने हर फिल्म में अपने किरदार को पूरी ईमानदारी और भावनाओं के साथ निभाने की कोशिश की है। यही वजह है कि उनके कई किरदार आज भी दर्शकों के बीच खास जगह रखते हैं।

रानी ने कही दिल छू लेने वाली बात

इस सम्मान के बाद रानी मुखर्जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनकी आवाज घर से बहुत दूर तक पहुंची हैं। उनके लिए यह सफर बेहद खास रहा है। रानी का यह सम्मान सिर्फ उनकी एक्टिंग को पहचान नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय सिनेमा की कहानियां अब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दर्शकों तक पहुंच रही हैं।

अनुपमा परमेश्वरन ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बोलीं-दो साल तक मैं एक रिश्ते में...

बीते दिनों अनुपमा परमेश्वरन ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को लेकर पोस्ट किया था। इससे फैंस को उनके ब्रेकअप का अंदाजा हो गया था। एक इंटरव्यू के दौरान आई एम धान्या वर्मा नाम के शो में उन्होंने अपने रिश्तों पर बात की। अनुपमा परमेश्वरन ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में दो साल तक चले एक रिश्ते में हुए दुर्व्यवहार का जिक्र है। उन्होंने इस बारे में तभी बात की जब उन्हें लगा कि वह अब इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अनुपमा ने कहा मैंने पिछले दो साल एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिताए जो कि आत्ममुग्ध था। सिर्फ अपनी परवाह करता था। मैंने यह पोस्ट तब शेयर किया जब मैं उस रिश्ते से बाहर आ गई। और अपने अनुभव के बारे में बात करने के लिए तैयार महसूस कर रही हूं। यह काम मैंने बस दो मिनट के गुस्से में नहीं किया। बल्कि यह सब कुछ मेरे अंदर काफी वक्त से चल रहा था। कुछ लोग इस अनुभव को समझते हैं क्योंकि उन्होंने इसे महसूस किया है। यह सब कुछ वो लोग भी समझ सकते हैं जिनके अपने या करीबी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो।

इस उत्पीड़न के कई स्टेज होते हैं

अपनी बातचीत में आगे अनुपमा परमेश्वरन ने कहा, 'पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जो पीड़ित लोगों को जानते हैं, यानी वे परिवार और मित्र जिन्होंने किसी को पीड़ित होते देखा है। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह शब्द सुना तो होगा, लेकिन इसके बारे में किसी तरह की कोई खोजबीन नहीं की हो। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो इसे जेंडर-आधारित बताते हैं और अनुमानों के आधार पर निगेटिव टिप्पणियां करते हैं। अगली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनसे मैं बात करना चाहती हूं, वे लोग जो इस स्थिति से गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इसे पहचान नहीं पाए हैं। यही सबसे ज्यादा खतरनाक है।'

अनुपमा परमेश्वरन ने कई महीनों पहले सोशल मीडिया से ब्रेक लया था। एक्ट्रेस के हालिया फेसबुक पोस्ट से फैंस को उनके तनाव में होने का अंदाजा लगा था। उन्होंने पोस्ट में खुद को चुनने और आजादी के बारे में लिखा था। इसे पढ़कर फैंस ने उनके और ध्रुव विक्रम के रिश्ते पर सवाल खड़े किए। हालांकि इस रिश्ते के बारे में न कभी अनुपमा ने कोई बयान दिया न ही ध्रुव ने ही अधिकारिक रूप से कुछ कहा। न ही अब तक अनुपमा ने उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसके साथ वह रिलेशनशिप में थीं।

इमरान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनी 'आवारापन 2'

लगभग 19 साल बाद इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल रिलीज हुआ है। पहले जब 'आवारापन' आई थी तो अपने गीतों और कहानी के कारण कल्ट फिल्म बन गई थी। इस क्रेज का फायदा सीक्वल को भी मिला है। इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनी 'आवारापन 2' बन चुकी है। इससे पहले उनकी किसी फिल्म ने ओपनिंग डे पर इतनी कमाई नहीं की थी। फिल्म 'आवारापन 2' के अभी 5,410 शो सिनेमाघरों में चल रहे हैं। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर क्रेज देखा जा रहा है।

वीर पहाड़िया ने प्रेम कीटाणु के साथ बढ़ाया अपना फ़िल्मी सफर

स्काई फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद वीर पहाड़िया लगातार बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करते जा रहे हैं और इसका सबूत है महेश भट्ट की नाम - टू लिव इज वॉर के बाद उनकी अगली थ्रिएट्रिकल फिल्म प्रेम कीटाणु, जिसकी घोषणा उन्होंने हाल ही में की है। इसी वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने जा रही यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में वीर पहाड़िया के साथ अपारशक्ति खुराना, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय भी नजर आएंगे।

'प्रेम कीटाणु' का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है, जो 'सिर्फ एक बंदा काफी है' और चर्चित सीरीज 'एसिपरेंट्स' के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म गौरव वर्मा के नए लॉन्च किए गए बैनर अवनिका फिल्म्स की पहली प्रोडक्शन है, जिसे फार्स फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी कहानी युवाओं की आकांक्षाओं, रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी एक दिल छू लेने वाली और रिलेटेबल एंटरटेनर है।

हास्य और भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में आधुनिक जीवन और प्यार को एक नए नजरिए से पेश करने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 'प्रेम कीटाणु' वीर पहाड़िया को उनके डेब्यू 'स्काई फोर्स' से बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करेगी।

'स्काई फोर्स' में उन्होंने भारतीय वायुसेना के अधिकारी टी. विजया का किरदार निभाया था। ऐसे में देशभक्ति और एक्शन से भरपूर ड्रामा के बाद अब युवा और रिश्तों पर आधारित एंटरटेनर का हिस्सा बनना दिखाता है कि वीर अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अलग-अलग तरह के किरदार और जॉनर तलाश रहे हैं। जैसा कि वीर की आगामी फिल्मों की लिस्ट में डार्क एक्शन थ्रिलर 'नाम - टू लिव इज वॉर' भी शामिल है।

महेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत और सिद्धांत सचदेव द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वीर के साथ वरुण शर्मा नजर आएंगे, जो पहली बार नेगेटिव भूमिका में दिखाई देने की उम्मीद है। फिल्म का निर्माण रिद्धि चावड़ा और उत्सव उपाध्याय कर रहे हैं। 'प्रेम कीटाणु' और 'नाम - टू लिव इज वॉर' के जरिए वीर पहाड़िया दो बिल्कुल अलग सिनेमाई दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। एक ओर जहां 'प्रेम कीटाणु' रोमांस, हास्य और युवा भारत की रोजमर्रा की वास्तविकताओं को सामने लाएगी, वहीं 'नाम - टू लिव इज वॉर' में उनका एक इंटेंस और रग्ड एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। 'स्काई फोर्स' के बाद इन दोनों फिल्मों की घोषणा वीर पहाड़िया के करियर के अगले चरण की ओर इशारा करती है, जहां अभिनेता किसी एक इमेज तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग जॉनर और किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

रणवीर ने शुरू की 'प्रलय' की शूटिंग, साउथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शनी भी आएगी नजर

फरहान अख्तर की 'डॉन 3' पर हुए तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए रणवीर सिंह ने रविवार से अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में लीड रोल निभाने के साथ ही रणवीर इस फिल्म से बतौर निर्माता भी जुड़े हैं। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद रणवीर सिंह का यह पहला प्रोजेक्ट है। इस फिल्म को लेकर अभिनेता के फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। 'प्रलय' को रणवीर के करियर का सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। इसे लाइव लोकेशन पर भी शूट किया जाएगा। रणवीर इस फिल्म में अभिनय करने के साथ ही इसका निर्माण भी कर रहे हैं। यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी। रणवीर के लिए यह महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिल्म में 'लोका' फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शनी भी अभिनय करती नजर आएंगी। बड़े पैमाने पर होगा काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'प्रलय' की कहानी काफी हद तक विजुअल इफेक्ट्स पर निर्भर करेगी। फिल्म में धुआंधार एक्शन सीन्स भी होंगे। रणवीर इस फिल्म के डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान क्रिएटिव चर्चाओं में भी एक्टिव रूप से शामिल हुए हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली 'प्रलय' रणवीर सिंह के करियर की सबसे महंगी स्टैंडअलोन फिल्म हो सकती है।

फिल्म 'प्रलय' के बारे में 'प्रलय' में रणवीर सिंह मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वहीं कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका निभाएंगी। फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं। वहीं फिल्म का निर्माण अनन्या बिड़ला स्टूडियोज कर रहा है।

...क्या ऋतिक-सबा का हुआ ब्रेकअप?

डेटिंग एप पर 'ग्रीक गॉड' की प्रोफाइल वायरल होने के बाद चर्चा शुरू

अभिनेता ऋतिक रोशन कई साल से सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर साथ में पार्टी और इवेंट में देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हैं। मगर, इन दिनों बी-टाउन में दोनों के ब्रेकअप की अटकलों ने जोर पकड़ा है। इसकी वजह ऋतिक रोशन की प्रोफाइल का कथित तौर पर एक डेटिंग एप पर देखा जाना है।

ऋतिक-सबा के ब्रेकअप की खबरों ने पकड़ा जोर

सुजैन खान से तलाक के बाद ऋतिक रोशन की जिंदगी में सबा आजाद की एंट्री हुई है। दोनों के बीच उम्र का काफी अंतर है। मगर, आपसी समझ काफी अच्छी है। अक्सर दोनों छुट्टियां मनाने जाते हैं। साथ में पार्टी करते हैं और बॉलीवुड के कई इवेंट्स में साथ में शिरकत करते हैं। मगर, इन दिनों ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों की राहें जुदा हो गई हैं।

क्यों शुरू हुई अटकलें

सबा से ऋतिक के रिश्ते में दूरी की वजह, एक डेटिंग एप पर अभिनेता की प्रोफाइल का पाया जाना है। दरअसल, 'राया' नाम के एक डेटिंग एप पर ऋतिक रोशन की प्रोफाइल होने का दावा किया गया है। इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल स्क्रीनशॉट में ऋतिक के प्रोफाइल बायो में 'एक्टर/ प्रोड्यूसर/ एंटरप्रेन्योर' लिखा दिख रहा है। इस वायरल प्रोफाइल के बाद ही ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या दोनों का ब्रेकअप हो गया है? हालांकि, रिलेशनशिप को लेकर चल रहीं अटकलों पर अभी तक ऋतिक रोशन और सबा आजाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

उर्वशी रौतेला ने भी किया था दावा

रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में उर्वशी रौतेला ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने सेलिब्रिटी डेटिंग एप 'राया' पर ऋतिक रोशन और आदित्य रॉय कपूर के प्रोफाइल देखे थे। हालांकि, उर्वशी रौतेला ने सीधे-सीधे ऋतिक रोशन के रिलेशनशिप स्टेटस से जोड़कर कोई टिप्पणी नहीं की थी। मगर, उर्वशी के पुराने बयान और अब वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर सबा और ऋतिक के रिश्ते में आई दूरी से जोड़कर देख रहे हैं। देखना होगा कि ऋतिक या सबा ऐसी अफवाहों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

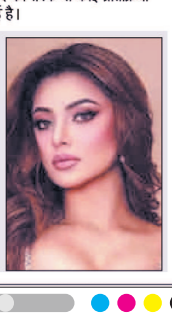

बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आदिवासी विकास से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के भविष्य को संवारने में शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचे।

नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

कलेक्टर ने जिले की सभी शालाओं में प्रवेशित बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल नामांकन कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे का नियमित रूप से स्कूल आना और पढ़ना-लिखना सीखना जरूरी है। इसके लिए शिक्षकों और पालकों के बीच नियमित संवाद एवं संपर्क बनाए रखने को कहा गया। उन्होंने स्कूलों में बच्चों के लर्निंग आउटकम पर विशेष ध्यान देने तथा कमजोर बच्चों के लिए नियमित रूप से रेमेडियल क्लास संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक क्षमता में सुधार हो सके।

मध्याह्न भोजन में पोषण पर विशेष फोकस

बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को केवल

पेट भर भोजन नहीं, बल्कि पौष्टिक एवं संतुलित आहार मिलना चाहिए। उन्होंने भोजन के मेन्यू में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल एवं अन्य पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और निर्धारित मेन्यू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शालाओं में रसोइयों की उपलब्धता तथा खाद्य सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

सितंबर तक शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश

आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए कलेक्टर ने सितंबर माह तक शत-प्रतिशत पात्र बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की समयसीमा निर्धारित की। उन्होंने बीईओ एवं तहसीलदारों को आपसी समन्वय कर स्कूल स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र बच्चा जाति प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रवृत्ति या अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।

बालिका सुरक्षा व स्वच्छता सर्वोपरि

कलेक्टर ने बालिका शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वच्छता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी शालाओं में बालिका शौचालयों का निर्माण अनिवार्य रूप से पूरा कराने तथा निर्मित शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावासों एवं आश्रमों में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों तथा महिला वार्डन की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही परिसर में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का रखें विशेष ध्यान

स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष, छात्रावास एवं शौचालय सहित स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरे किए जाएं। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्य पूर्ण होने से पहले तृतीय पक्ष से गुणवत्ता जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी स्कूलों एवं छात्रावास परिसरों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरा-भरा रखने पर भी जोर दिया।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), बीआरसी एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने सभी अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के भीतर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

खास खबर

अंबागढ़ चौकी में बाढ़ आपदा से बचाव व राहत कार्यों का किया व्यावहारिक अभ्यास

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के निदेशानुसार जिला स्तर पर बाढ़ आपदा से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 20 अगस्त को शिवनाथ नदी, अंबागढ़ चौकी में मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। मॉक एक्सरसाइज के दौरान बाढ़ की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के संचालन, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सहित आपदा प्रबंधन की तैयारियों का व्यावहारिक अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास के सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मॉक एक्सरसाइज की तैयारियों का जायजा लेने अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सौंपे गए दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मॉक एक्सरसाइज का प्रभावी एवं व्यवस्थित संचालन किया जा सके।

कलेक्टर वर्मा को दी गई विदाई, नवीन पदस्थापना पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने दी शुभकामनाएं

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

राज्य शासन द्वारा नवीन पदस्थापना किए जाने के फलस्वरूप कलेक्टर गोपाल वर्मा को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विदाई दी गई। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित अधिकारियों-कर्मचारियों ने श्री वर्मा को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनकी नवीन पदस्थापना के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कलेक्टर वर्मा ने कबीरधाम जिले में कलेक्टर के रूप में 22 माह 28 दिन तक अपनी सेवाएं दीं। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नवीन पदस्थापना वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर की गई है।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा, पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर, बोड़ला एसडीएम आशुतोष शर्मा, एमडी जीएस शर्मा, तहसीलदार परमेश्वर मंडावी, अधीक्षक राजेन्द्र ध्रुवे सहित अन्य अधिकारियों ने श्री वर्मा के कार्यकाल से जुड़े अनुभव साझा किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विदाई समारोह के दौरान कहा कि उन्हें जिले में काम करने के दौरान सभी अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि इस सहयोग की वजह से कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका और विकास के कार्यों में तेजी आई। उन्होंने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी जिले की प्रगति के लिए ऐसे ही सहयोग की भावना बनी रहेगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करें और जनसामान्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहे। इस अवसर अपर कलेक्टर आंचला, सागर सिंह, कवर्धा एसडीएम चेतन साहू, नायब तहसीलदार विकास जैन सहित जिला अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

केविके बेमेतरा में टीसीबीटी प्राकृतिक खेती तकनीक पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

60 से अधिक प्रगतिशील कृषकों ने लिया प्रशिक्षण, प्राकृतिक खेती की तकनीकों और कम लागत वाले कृषि आदानों की दी गई जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा में किसानों को प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने के उद्देश्य से ताराचंद बेलजी तकनीक प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों, प्राकृतिक कृषि आदानों के निर्माण एवं उपयोग, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक कीट प्रबंधन तथा कम लागत में टिकाऊ कृषि उत्पादन के संबंध में किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस श्री ताराचंद बेलजी ने TCBT प्राकृतिक खेती तकनीक की अवधारणा एवं इसके व्यावहारिक पहलुओं पर किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पतवार रसायन के संबंध में जानकारी देते हुए इसके निर्माण, उपयोग की विधि तथा फसलों में प्रयोग से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा की। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कीट विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. गजेंद्र चंद्राकर ने प्राकृतिक खेती में जैविक एवं प्राकृतिक उपायों से कीट प्रबंधन तथा फसल सुरक्षा के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की। TCBT प्रशिक्षक रविकांत साहू ने विभिन्न प्राकृतिक कृषि आदानों की प्रायोगिक विधि एवं उपयोग की जानकारी देते हुए अन्न द्रव्य रसायन के बारे में विस्तार से समझाया। वहीं TCBT विशेषज्ञ रणवीर ने प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों, विशेष रूप से जैव रसायन तथा खेत स्तर पर इनके उपयोग की जानकारी किसानों को दी।

कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तोषण कुमार ठाकुर ने किसानों को प्राकृतिक खेती में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के उपयोग से कृषि की उत्पादन लागत को कम करने के साथ-साथ किसानों की आय और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार करने, मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने, प्राकृतिक तरीके से कीट प्रबंधन करने तथा फसल उत्पादन में स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बेमेतरा जिले के जैविक एवं प्राकृतिक खेती से जुड़े 60 से अधिक प्रगतिशील कृषक शामिल हुए। किसानों ने TCBT तकनीक एवं अपने प्रक्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं को विशेषज्ञों के समक्ष रखा तथा उनके तकनीकी समाधान की जानकारी प्राप्त की। तकनीकी सत्र का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डोमन सिंह टेकाम एवं डॉ. रजनी डी. अगाशे ने किया।

प्रशिक्षण उपरांत अतिथियों एवं किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रदर्शनी कक्ष का अवलोकन किया। यहां प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों, जिले के प्रगतिशील किसानों द्वारा किए जा रहे नवाचारों तथा केविके द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती इकाई, बीज उत्पादन इकाई, हाईटेक नर्सरी एवं मछली पालन इकाई सहित विभिन्न गतिविधियों का भ्रमण किया गया। अतिथियों एवं किसानों ने केविके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिए।

प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान अतिथियों द्वारा प्राकृतिक खेती में उपयोगी कृषि आदानों के लिए बहुउपयोगी वृक्षों का पौधारोपण किया गया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में TCBT तकनीक के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थल का निरीक्षण एवं चयन भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र जोशी, डॉ. लव, डॉ. चंद्रशेखर खरे तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी व्ही.के. टंडन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के आयोजन पर पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव का जताया आभार

प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच, रजिस्ट्रेशन शुरू

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होने जा रही छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ हॉकी के पदाधिकारियों ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार हॉकी लीग का आयोजन हॉकी और खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस लीग के जरिए प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा और बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए प्रदेश भर के खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों को लीग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आयोजन से प्रदेश में हॉकी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिलेगा।

श्री अंसारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हॉकी की गौरवशाली परंपरा रही है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। ऐसे में यह लीग प्रदेश में हॉकी के विकास को नई गति देगी।

पदाधिकारियों ने इस आयोजन के लिए प्रदेश सरकार और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के सहयोग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार के मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में हॉकी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध होंगे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी, महासचिव मनीष श्रीवास्तव, जिला हॉकी संघ राजनांदगांव के सचिव शिवनारायण धकेता, भूषण साव, नीलमचंद जैन, अनुराज श्रीवास्तव, अमिताभ मानिकपुरी, धनीराम यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जल जीवन मिशन की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, लंबित कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा पर जोर

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्ष सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के दिशा सभाकक्ष में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों की प्रगति, समूह जलप्रदाय योजनाओं, फंड रिलीज, CIRP, हर घर जल अभियान तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सहित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में SNA Sparsh के अंतर्गत देयकों के भुगतान तथा 7 जुलाई 2026 के उपरांत प्राप्त आवंटन के विरुद्ध किए गए भुगतानों के अनुमोदन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों से योजनावार प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने लंबित वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सुश्री ममगाई ने कहा कि जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। प्रगतिरत समूह जलप्रदाय योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षित गति से कम है, उनमें आ रही बाधाओं को चिन्हांकित कर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने, अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण करने तथा प्रत्येक परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने कहा। कार्यों में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

हर घर जल अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पात्र ग्रामीण परिवारों तक कार्यशील नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ नियमित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी समन्वय बनाए रखने और मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती प्रेमलता पदमाकर, पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता जेपी गोंड, सीएसपीडीसीएल के जेएस भटनागर, कृषि उपसंचालक एमडी डड़सेना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यशाला महिला सशक्तिकरण और योजनाओं पर मार्गदर्शन, बाल संरक्षण व चाइल्ड हेल्पलाइन की दी गई जानकारी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला व बाल कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के कुशल निर्देशन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिले के सभी 46 सेक्टरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 27 जुलाई से 1 सितंबर 2026 तक संवेदीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सेक्टर नवागांव कला एवं सेक्टर कन्हेरा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ग्राम खाती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न शाखाओं द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा विभागीय सेवाओं की विस्तृत जानकारी देना रहा, ताकि वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों एवं पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से दिला सकें। कार्यशाला में सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती मीना शर्मा सहित विभागीय

अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला परियोजना समन्वयक श्री राजेंद्र चंद्रवंशी ने बाल अपराध रोकथाम एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पॉक्सो एक्ट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल अपराध की स्थिति में तत्काल सूचना तंत्र सक्रिय करने पर जोर दिया।

उन्होंने बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों की पहचान कर समय पर रेस्क्यू एवं पुनर्वास से जोड़ने, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को चिन्हित कर पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने तथा बच्चों और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फॉस्टर केयर योजना की पात्रता एवं दिशा-निर्देशों तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की 24/7 आपातकालीन सुरक्षा, परामर्श एवं सहायता सेवाओं की कार्यप्रणाली से भी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया।

जेंडर विशेषज्ञ, मिशन शक्ति श्रीमती सेवतिका साहू ने महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों तथा महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सक्षम ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

कार्मिक वकील, सखी वन स्टॉप सेंटर श्रीमती रामेश्वरी साहू ने हिंसा एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं के लिए उपलब्ध सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे 24 घंटे आपातकालीन सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, परामर्श एवं अस्थाई आश्रय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने कार्यकताओं से अपील की कि वे जरूरतमंद महिलाओं को इन सेवाओं की जानकारी देकर उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

जिला बाल संरक्षण इकाई की आउटरीच वर्कर श्रीमती अनीता सोनवानी ने दत्तक ग्रहण एवं विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अनाथ, लावारिस एवं समर्पित बच्चों के वैध दत्तक ग्रहण के लिए उअफ्का की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता बताई तथा अवैध दत्तक ग्रहण की रोकथाम पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जिला बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तार से बताया तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए दोनों न्यायपीठों की भूमिका से कार्यकताओं को अवगत कराया। कार्यशाला के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकताओं को विभागीय योजनाओं एवं बाल एवं महिला संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाने तथा जरूरतमंद हितग्राहियों को समय पर शासकीय सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

यातायात पुलिस की सख्ती : 15 दिन में 1960 वाहनों पर की गई कार्रवाई

ब्रेकडाउन वाहनों को तत्काल सहायता, जानबूझकर सड़क रोकने वालों पर चालान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस रोड पर यातायात सुगम बनाने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस ब्रेकडाउन वाहनों को तत्काल सहायता दे रही है, साथ ही अनावश्यक रूप से सड़क रोकने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है।

पिछले 15 दिन का आंकड़ा

यातायात पुलिस के अनुसार पिछले 15 दिनों में कुल 216 ब्रेकडाउन वाहनों को सड़क से सुरक्षित हटाकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं 1960 वाहनों/चालकों के विरुद्ध बिना उचित कारण वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई।

कैसे हो रही मदद

यातायात पुलिस ने बताया कि ब्रेकडाउन की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचती है। वाहन चालक की समस्या सुनकर तकनीकी खराबी या आकस्मिक स्थिति का सत्यापन किया जाता है। वास्तविक खराबी होने पर वाहन को सुरक्षित हटाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

इन कारणों पर हो रही सख्त कार्रवाई

जांच में यदि डीजल समाप्त होना, चालक का अनुपलब्ध होना या बिल्टी-दस्तावेज के लिए प्रतीक्षा जैसे कारणों से जानबूझकर मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है, तो उसे लापरवाही मानकर वाहन चालक/मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

यातायात पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वास्तविक ब्रेकडाउन की स्थिति में तत्काल यातायात पुलिस को सूचना दें। अनावश्यक रूप से सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

40 साल का करंज का पेड़ 1 साल में मरा

अनुपम नगर में कांक्रीटीकरण बना वजह

वृक्षों के चारों ओर कांक्रीट पर प्रतिबंध के बावजूद जारी है लापरवाही

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

अनुपम नगर में एक 40 वर्ष पुराने करंज के पेड़ का 1 साल के भीतर जमीन से उखड़ जाना, नगरीय निकायों की वृक्ष संरक्षण नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

अगस्त 2025 की तस्वीर में दिख रहा है कि फुटपाथ के कांक्रीटीकरण के दौरान इस पेड़ के तने से सटाकर कांक्रीट कर दिया गया था। इससे पेड़ के आसपास की खुली मिट्टी और वर्षा जल का प्राकृतिक प्रवेश क्षेत्र खत्म हो गया। अगस्त 2026 की तस्वीर में यही पेड़ जड़ सहित गिरा हुआ मिला। खास बात ये कि पेड़ तब गिरा जब हवा भी तेज नहीं थी।

कंक्रीट कैसे मारता है पेड़ को

विशेषज्ञ बताते हैं कि कंक्रीट और पेवर से पेड़ के चारों ओर की मिट्टी ढक जाने पर जड़ों को पानी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पेड़ बाहर से कुछ समय तक हरा दिखता है, लेकिन धीरे-धीरे जड़ें कमजोर होकर पेड़ गिर जाता है। साथ ही वर्षाजल जमीन में नहीं जा पाता जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी प्रभावित होता है।

2019 में ही जारी हो चुके हैं निर्देश

रायपुर निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने बताया कि वृक्षों के चारों ओर कांक्रीटीकरण का मामला उन्होंने 2019 में ही उठाया था। इसके बाद 21 नवंबर 2019 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए थे कि पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर का क्षेत्र खुला छोड़ा जाए और भविष्य में कंक्रीट/पेवर न किया जाए। 2025 में ऑक्सीजोन रायपुर में पेड़ों के चारों ओर 5 फीट की दीवार बनाने की शिकायत भी हुई थी। इसके बावजूद अनुपम नगर में कंक्रीट का काम होता रहा।

यूरोप हटा रहा है कंक्रीट, हम लगा रहे हैं

सिंघवी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में पुराने पेड़ छाया, तापमान नियंत्रण और कार्बन अवशोषण के लिए जरूरी हैं। यूरोप के कई शहर Urban Heat Island Effect कम करने के लिए कंक्रीट और पेवर हटा रहे हैं, जबकि हम अभी भी पेड़ों को कंक्रीट में कैद कर रहे हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि "विकास की कीमत पर अगर पेड़ खत्म हुए तो 2027 से ही रायपुर की जनता को बढ़ते तापमान और कम छाया का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।"

मुख्य सचिव से की मांग

सिंघवी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी नगरीय निकायों में पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर से 3 मीटर तक का कांक्रीट/पेवर तत्काल हटाया जाए और भविष्य में जड़ों के आसपास किसी भी तरह का अभेद्य निर्माण न हो।

सिंधी सेवा महिला विंग ने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ . ममता साहू से की सौजन्य मुलाकात, अध्यक्ष बनने पर दी बधाई और शुभकामनाएं

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू से छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महिला विंग की टीम ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान महिला विंग की पदाधिकारियों ने डॉ. ममता साहू को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही महिलाओं के उत्थान और महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई।

इस अवसर पर भावना कुकरेजा के साथ साधना गुरनानी, कुसुम डोडवानी, कुसुम, अनीता, हेमा, पाखी, मंजू, ज्योति सहित सिंधी समाज की अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं।

डॉ. ममता साहू ने सभी का स्वागत करते हुए महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।

कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की दबिश

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जांच, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले

नई दृष्टिबिंदु / धमतरी

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार सुबह धमतरी में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर छापामार कार्रवाई की। यह कार्रवाई कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम सुबह करीब 8 बजे दो वाहनों में सुरक्षा बलों के साथ अग्रवाल के घर पहुंची। टीम में लगभग 8 अधिकारी और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने घर में मौजूद दस्तावेजों, बैंक और वित्तीय रिकॉर्ड तथा शराब घोटाले से संबंधित अन्य अभिलेखों की गहन जांच शुरू की।

फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। बरामद दस्तावेजों या अन्य सामग्री के संबंध में एजेंसी की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही बरामदगी और कार्रवाई के निष्कर्ष स्पष्ट हो पाएंगे। रामगोपाल अग्रवाल पूर्व में कांग्रेस के जिला कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। ईडी की इस दबिश के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चचाओं का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला लंबे समय से जांच के दायरे में है और ईडी पहले भी प्रदेश के कई नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

महंत कान्हा महाराज को रुद्र सेना के प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी

भिलाई। धर्म स्तंभ काउंसिल द्वारा महंत कान्हा महाराज पीठाधीश्वर को रुद्र सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी राजीव लोचन दास महाराज के संरक्षण एवं आशीर्वाद तथा रुद्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष अलोक पाण्डेय की अनुशंसा पर उन्हें प्रदेश महामंत्री रुद्र सेना (दुर्ग संभाग प्रभारी) पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है। नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि महंत कान्हा महाराज धर्म परायण, कर्मनिष्ठ एवं समाजसेवी हैं। संगठन ने उनके अनुभव और सामाजिक-धार्मिक कार्यों को देखते हुए यह दायित्व सौंपा है। नियुक्ति के बाद समर्थकों एवं अनुयायियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100